A Daily News Magazine

इंदौर

बुधवार, 21 जनवरी, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 111, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

टैरिफ के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर छू सकती है नई ऊंचाइयां

प्रह्लाद सबनानी

दिनांक 1 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के पूर्व वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के आर्थिक विकास से संबंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़े 7 जनवरी 2026 को जारी किए गए हैं। इस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल हुई थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। सकल घरेलू उत्पाद से सम्बंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के आधार पर ही वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आर्थिक विकास से सम्बंधित द्वितीय अग्रिम अनुमान 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाने हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान भी 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का ही है परंतु भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग का अनुमान 7.5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का है। भारत की आर्थिक विकास दर विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे अधिक रहने की सम्भावना विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन विकास बैंक (7.2 प्रतिशत), फिच नामक रेटिंग संस्थान (7.4 प्रतिशत) आदि संस्थानों ने भी व्यक्त की है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में हासिल की गई 6.5 प्रतिशत की वृद्धि से आगे बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के कुछ मुख्य कारणों में शामिल हैं - (1) केंद्र सरकार के स्थिर उपभोग खर्च (Govt Fixed Consumption Expenditure) में वृद्धि दर जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.3 प्रतिशत की रही थी, वह बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (2) विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.5 प्रतिशत की रही थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.0 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (3) सकल मान योग (Gross Value Addition) में वृद्धि दर का 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है; (4) सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) में वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है; (5) सेवा एवं कृषि क्षेत्र में क्रमशः 9.1 प्रतिशत एवं 3.1 प्रतिशत की सम्भावना व्यक्त की गई है; (6) भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर का 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना होना भी शामिल है। अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 के खंडकाल में राजकोषीय घाटा 9.8 लाख करोड़ का रहा है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल अनुमान का 62.3 प्रतिशत है, अतः बजटीय घाटा भी अभी तक नियंत्रण में ही रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत होगा। इस प्रकार केंद्र सरकार की आय एवं व्यय से सबंधित स्थिति भी पूर्णतः नियंत्रण में है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत के अनुमान को उत्साहवर्धक माना जाना चाहिए क्योंकि यह वृद्धि दर ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद रहने वाली है। दरअसल ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ को वित्तीय बाजार में बहुत गम्भीरता से लिया जाकर इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। परंतु, वास्तव में भारत के आर्थिक विकास दर पर इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिका को भारत से होने वाले निर्यात की कम मात्रा भी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका को 7900 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विभिन्न वस्तुओं के निर्यात हुए थे, जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.29 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा था। अतः भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.85 प्रतिशत ही रहे हैं। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है ही नहीं (चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, इसीलिए चीन पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव अधिक हो सकता है), भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः आंतरिक उपभोग पर आधारित है। यदि भारत के नागरिक स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपभोग करते हैं तो ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को शून्य भी किया जा सकता है।

किसी भी देश के नागरिक यदि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना प्रारम्भ करते हैं तो इससे देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात कम होता है और देश में ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। स्वदेशी का मतलब विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करना है परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है क्योंकि आज विश्व के समस्त देश एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गए हैं, जिसके चलते उत्पादों का एक देश से दूसरे देश में आयात एवं निर्यात बहुत आसान बन पड़ा है। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं स्वदेशी का अर्थ है-आत्मनिर्भरता और अहिंसा। संघ ने इसमें एक बिंदु जोड़ दियाः सादगी। प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह मितव्ययिता से जिए ताकि संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सके। परंतु, इसका आश्य कंजूसी कदापि नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक संगठनों के साथ ही केंद्र सरकार ने भी आर्थिक क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं जिसके चलते हाल ही के समय में भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि दर में लगातार सुधार दिखाई दिया है। विशेष रूप से ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ के प्रभाव को लगभग शून्य करने के उद्देश्य से भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इनमे विशेष रूप से शामिल हैं यूनाइटेड किंगडम, ओमान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि। यूरोपीयन देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता शीघ्र ही सम्पन्न होने जा रहा है। सम्भवत 27 जनवरी 2026 को इस मुक्त व्यापार समझौते पर यूरोपीयन यूनियन एवं भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही, अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ से प्रभावित होने वाले उत्पादों के लिए भारत ने अन्य देशों के रूप में बाजार तलाश लिए हैं एवं इन देशों को विभिन्न उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ हो चुका है जिससे नवम्बर 2025 एवं दिसम्बर 2025 माह में भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर हासिल की जा सकी है

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

भाजपा में अब नितिन नबीन युग

भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने

पीएम मोदी बोले- मैं कार्यकर्ता, वे मेरे बॉस, अब मेरे काम का आंकलन करेंगे

राजनीति कोई पदभार नहीं, उत्तरदायित्व है : नितिन नबीन

नई दिल्ली (एजेंसी)। नितिन नबीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया।

मोदी ने 55 मिनट के भाषण में कहा 'भाजपा ऐसी पार्टी है, जहां लोगों को लगता होगा कि मोदीजी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए हैं। इन सबसे बड़ी चीज है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि नितिनजी मेरे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता हूं। अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे।'

अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन ने अपने पहले भाषण में कहा, 'हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं, जहां राजनीति सत्ता नहीं, साधना है। राजनीति भोग नहीं, त्याग है। राजनीति ऐशो-आराम नहीं, तपस्या है। राजनीति कोई पदभार नहीं, उत्तरदायित्व है।' नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

कांग्रेस अपने पतन की जिम्मेदार

'आज देश को याद भी नहीं होगा कि 1984 में कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें मिली थीं और देश ने कांग्रेस को करीब-करीब 50 प्रतिशत वोट दिया था, लेकिन आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे और पतन के कारणों पर जाएंगे तो उसी परिवार पर सवाल उठेंगे।

घुसपैठियों को देश लूटने नहीं देगा

आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है। दुनिया के समर्थ देश भी अपने देश में घुसपैठियों की जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़-पकड़ कर निकाल रहे हैं।

महाराष्ट्र नतीजों ने बताया भाजपा पहली पसंद

भाजपा सिर्फ संसद और विधानसभा की ही नहीं, बल्कि नगरपालिकाओं और नगर निगमों में भी पहली पसंद है।

पिछले डेढ़ साल में जीते 4 राज्यों में चुनाव

'बीते डेढ़-दो वर्षों में भाजपा पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, भाजपा की स्ट्राइक रेट अभूतपूर्व रही है। इस दौरान देश में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनमें से 4 चुनाव भाजपा-एनडीए ने जीते हैं।'

पीएम मोदी ने भाजपा अध्यक्ष को पदभार ग्रहण कराया मिठाई खिलाई, अध्यक्ष के परिवार से भी मिले

नितिन नबीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को इसका आधिकारिक ऐलान हुआ। इसके बाद पीएम मोदी उन्हें पार्टी अध्यक्ष के दफ्तर लेकर गए। पदभार ग्रहण करवाया। मिठाई खिलाई और उनके परिवार से भी मिले।

मुख्यमंत्री का दावोस में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर केन्द्रित सत्र का संबोधन

विरासत, विकास और निवेश के अवसरों के संगम से उभरता मप्र

भोपाल (नप्र)। देश का हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। प्रदेश, प्रकृति की अनुपम सुंदरता, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, गहन आध्यात्मिक आस्था और विविध वन्य जीवों का अद्भुत संगम है। इन्हीं विशेषताओं और निवेश संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित सत्र को संबोधित करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकास भी, विरासत भी के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश ने पर्यटन को समावेशी और सतत विकास के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित किया है। इसके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में प्रदेश में 13.30 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है, जो मध्यप्रदेश के प्रति बढ़ते राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है।

आध्यात्मिक पर्यटन मध्यप्रदेश की प्रमुख पहचान के रूप में स्थापित हुआ है। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में 6.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। इसके साथ ही खजुराहो, सांची, ओरछा, महेश्वर, अमरकंटक और चित्रकूट जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल देश-विदेश के पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र बने हुए हैं।

डब्ल्यूईएफ-दावोस-दूसरा दिन

श्रीलंकाई उद्योग समूह जॉन कील्स के साथ निवेश अवसरों पर हुई चर्चा

भोपाल (नप्र)। वर्ल्ड इकोनॉमिक दावोस यात्रा के दूसरे दिन प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार श्री मनीष सिंह ने श्रीलंका के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह जॉन कील्स होल्डिंग्स पीएलसी के चेयरमैन श्री कृष्णन बालेंद्र के साथ मीटिंग की। उन्होंने राज्य में निवेश एवं सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में लॉजिस्टिक्स, आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी), खाद्य प्रसंस्करण एवं पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मध्यप्रदेश में उपलब्ध अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकार द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु लागू नीतियों एवं उपलब्ध प्रोत्साहनों की जानकारी भी प्रतिनिधिमंडल के साथ साझा की गई। जॉन कील्स समूह ने भारतीय कंपनियों के साथ अपने मौजूदा व्यावसायिक जुड़ाव तथा भारत में विभिन्न टाई-अप्स के माध्यम से अपने व्यापार की जानकारी दी। प्रमुख सचिव श्री सिंह ने राज्य की अनुकूल निवेश नीति, मजबूत अवसंरचना, कुशल मानव संसाधन एवं उद्योग-अनुकूल वातावरण को रेखांकित करते हुए जॉन कील्स समूह को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

शरद की सुबह

फिर से तपते हुए दिनों की शुरुआत
हवा में अजीब-सी गंध है
और डोमों की चिता
अभी भी दहक रही है
वे कह रहे हैं
एक माह तक मुफ्त राशन
मृतकों के परिवार को
और लकड़बग्घा हंस रहा है...
और मैं...
फिर से खड़ा हूं
इस अंधेरी रात की नब्ज़ को
थामे हुए
कह रहा हूं
ये तीमारदार नहीं
हत्यारे हैं
और वह आवाज़
खाने की मेज़ पर
बच्चों की नहीं
लकड़बग्घे की हंसी है
सुनो...
यह दहशत तो है
चुनौती भी
लकड़बग्घा हंस रहा है।

- चंद्रकांत देवताले

कुमाऊं में सूखे की मार, पर्वतीय जिलों में स्थिति गंभीर

100 दिन से नहीं बरसे बादल, 15 दिन में बारिश नहीं हुई तो फसल हो जाएगी बर्बाद

नैनीताल (एजेंसी)। कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में 100 दिन से अधिक समय से बारिश और बर्फबारी नहीं होने के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। फल पट्टी और रबी की फसलें सूखने के कगार पर हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 15 दिनों में बारिश नहीं हुई तो 40 प्रतिशत तक फसल बर्बाद हो सकती हैं।

कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 207512 हेक्टेयर में रबी की फसल की बुवाई हुई है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर और तिलहन शामिल हैं। प्रारंभिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि पहले ही 15-20 प्रतिशत तक फसल का नुकसान हो चुका है, खासकर वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में। पर्वतीय जिलों में स्थिति गंभीर है, जहां सिंचाई के साधन सीमित हैं। कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन करने के लिए टीमों का गठन किया है और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा देने की तैयारी कर रहा है।

बारिश नहीं होने से सबसे अधिक पहाड़ों की फसलें प्रभावित

कृषि विभाग कुमाऊं मंडल के संयुक्त निदेशक पीके सिंह ने बताया कि पिछले 100 दिनों से अधिक समय से बारिश नहीं होने से रबी की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। प्रथम चरण में नजरी सर्वे किया गया है। जिसके तहत करीब 15 प्रतिशत तक फसलों का नुकसान का आकलन किया गया है। सबसे अधिक नुकसान पर्वतीय जिलों में हुआ है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ बुधवार, 21 जनवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

इंजीनियर मौत मामले में एमजेड विश्टाउन कंपनी का मालिक बिल्डर अभय सिंह अरेस्ट

नोएडा (एजेंसी)। नोएडा में 27 वर्षीय इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत मामले में पुलिस ने आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डर अभय सिंह एमजेड विश्टाउन

के मालिक हैं। एफआईआर में दो बिल्डर एमजेड विश्टाउन और लोटस ग्रीन को नामजद किया गया है। नालेज थाना पार्क पुलिस ने ये कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सोमवार को आईएएस अफसर लोकेश एम. को नोएडा प्राधिकरण के मुख्य अधिशासी अधिकारी के पद से हटा दिया था। उनको वेटिंग में रखा गया है।

तीन दिन से धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस

- मेला प्राधिकरण ने कहा- 24 घंटे में साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं

प्रयागराज (एजेंसी)। प्रयागराज में रथ रोकने के विरोध में धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। मेला प्राधिकरण ने उन्हें 24 घंटे में यह साबित करने को कहा है कि वे

ही असली शंकराचार्य हैं।

सोमवार रात 12 बजे कानूनगो अनिल कुमार माघ मेला में शंकराचार्य के शिविर पहुंचे। उन्होंने शंकराचार्य के शिष्यों से नोटिस लेने के लिए कहा। शिष्यों ने नोटिस लेने से मना कर दिया। कहा- इतनी रात में कोई नहीं हैं। सुबह आइएगा। कानूनगो अनिल कुमार मंगलवार सुबह फिर शंकराचार्य शिविर पहुंचे। वहां गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है। दरअसल, ज्योतिषपीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंद के बीच विवाद है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

खाटूश्यामजी से लौट रहे मां-बेटे और बहू की मौत

- तेज रफ्तार कार कंटेनर में घुसी, 7 गंभीर घायल, दिल्ली हाईवे पर जाम लगा

जयपुर (एजेंसी)। जयपुर में हुए एक भीषण एक्सीडेंट में कार सवार मां-बेटे और बहू की मौके पर ही मौत हो गई। खड़े कंटेनर में घुसी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। एक्सीडेंट में कार सवार 7 लोग गंभीर घायल हुए हैं। इनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। एक्सीडेंट जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे-48 पर चंदवाजी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह 11 बजे हुआ। हादसे के कारण कुछ देर के लिए हाईवे पर जाम भी लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की स्पीड ज्यादा थी। कार में सवार महिला और अन्य लोग उसमें ही फंस गए।

दिल्ली की तरफ जा रही थी कार- हीरालाल सैनी ने बताया- हादसा चंदवाजी पुलिया से एक किलोमीटर पहले हाईवे पर बिलपुर में हुआ।

बीजेपी हिंदुओं और ओवैसी मुलसमानों को डराकर राजनीति करते : दिग्विजय सिंह

पूर्व सीएम ने कहा- सावरकर और जिन्ना ने देश का बंटवारा कराया अब मोहल्ले बंट रहे

भोपाल (नप्र)। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं, बल्कि हिंदुत्व के साथ खड़ी है।

दिग्विजय सिंह ने कहा-हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, यह केवल एक पहचान है। भाजपा लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है।

बीजेपी हिंदू धर्म के साथ नहीं, हिंदुत्व के साथ- दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर कर कहा - भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं हैं हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व धर्म नहीं हैं ये पहचान है, उन्होंने जो कहा है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जगह-जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हम से ही चंदा ले रहे हैं और हमको ही भंडारा खिला रहे हैं। ये कौन सा धर्म है।

बीजेपी-आरएसएस हिंदुओं और ओवैसी मुसलमानों को डराते हैं- दिग्विजय सिंह ने कहा- भाजपा और आरएसएस इनका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। ये केवल लोगों को डराते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में हैं और ओवैसी कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ हिंदुओं से खतरा है। दोनों मिलकर खेल खेलते हैं। न हिंदुओं को खतरा है न मुसलमानों को खतरा है।

सावरकर और जिन्ना ने देश का बंटवारा कराया, अब मोहल्लों के बंटवारे हो रहे- पूर्व सीएम ने आगे कहा- आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है। इस बात को समझो देश को बचाओ। सावरकर जी ने और मुहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार.... अब देश का बंटवारा नहीं, यहां मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है। शहरों में

बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसी हो गई हैं कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया हिन्दुओं ने अपना मोहल्ला बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है?

हम सब एक हैं सबका मालिक एक है। हम लोग भारतीय हैं भारत वर्ष हमारे संविधान में दिया हुआ हमारे देश का नाम है।

हिंदू शब्द वैदिक नहीं, फारसी है- दिग्विजय सिंह ने कहा- हिंदू शब्द कहां से आया है ये वैदिक शब्द नहीं हैं। ये फारसी शब्द है। जब भारसी भाषा यहां आई तो फारसी लोग स को ह कहते हैं तो सिंध नदी के इस पार जो लोग रहते थे वो लोग हिंदू कहलाने लगे। इसलिए मोहन भागवत ठीक कहते हैं हिंदू-मुसलमान, हिंदू-ईसाई, हिंदू-सिख। बात वही है कि हिंदू धर्म नहीं है, ये एक भौगोलिक शब्द है। हमारा धर्म सनातन है।

जिसका अंत नहीं वो सनातन

दिग्विजय सिंह ने कहा- सनातन का मतलब क्या होता है जिसका कोई अंत नहीं वो सनातन है। सनातन धर्म में हजारों वर्ष से इस बारे में विवाद हुआ चर्चा हुई उसका निचोड़ सनातन धर्म में यही है अद्वैत वेदांत। इसमें आदि शंकराचार्य ने दो हजार साल पहले हमारे चार मठ स्थापित किए। इसका मतलब ये है कि नर ही नारायण है मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं हैं। यहां हृदय में नारायण है इन्हें सनातन की परिभाषा कौन समझाए?

हमारी आस्था का प्रतीक मणिकर्णिका घाट तोड़ा

दिग्विजय ने कहा- ये हिंदुत्व के साथी हैं सनातन धर्म के साथी नहीं हैं। अगर होते तो परंपरागत हजारों वर्ष से एक आस्था का प्रश्न है कि मणिकर्णिका घाट पर हमारा दाह संस्कार होगा तो हमें मोक्ष मिलेगा। ये हमारी आस्था का प्रश्न है कि हमारी अस्थियां मणिकर्णिका घाट पर गंगा जी में प्रवाहित हो तो मोक्ष मिलेगा। उस मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया।हमारे लिए तो ये और दुख की बात है कि मां अहिल्या जिन्होंने सनातन धर्म के लिए हर तरह से काम किया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उनकी प्रतिमा तोड़ दी और उनका महल तोड़ दिया। ये क्या हमारा सनातन धर्म है? ये नरेन्द्र मोदी और मोहन भागवत से प्रश्न करता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं वो सनातन धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं। हिंदुत्व का शब्द सावरकर जी ने दिया उन्होंने कहा था ये धर्म नहीं हैं ये पहचान है।

गुजरात के सूरत में उद्घाटन से पहले गिरी 21 करोड़ की पानी की टंकी

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के सूरत में 21 करोड़ रुपये के लागत से बनाई गई टंकी के टेस्टिंग के दौरान गिरने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से पानी की टंकी गिरने का वीडियो को साझा करते हुए लिखा है एक तरफ कांग्रेस के शासन

काल में बनाई गई पानी की टंकी जेबीसी से तोड़नी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के शासन काल में बनी टंकी उद्घाटन से पहले ही गिर गई। कांग्रेस पार्टी ने सूरत के ताड़केश्वर के पानी की टंकी गिरने का वीडियो भी साझा किया है। पानी की टंकी गिरने पर तीन मजदूर भी घायल हो गए थे। इस पानी की टंकी की टेस्टिंग 19 जनवरी को की गई थी। जानकारी के अनुसार इस जल आपूर्ति विभाग ने बनाया था। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में कांग्रेस मॉडल-बीजेपी मॉडल लिखाकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने जिस पानी की टंकी का हवाला दिया है वह 70 साल पुरानी थी। जिसे बुलडोजर से तोड़ना पड़ा था।

नोएडा हादसे को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर सीधा हमला

सड़कें, पुल और भ्रष्टाचार जान ले रहे हैं

नोएडा (एजेंसी)। नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नोएडा के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया है और एसआईटी का गठन कर पांच दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है तो वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोई जवाबदेही नहीं है।

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी ने लिखा, सड़कें जान ले रही हैं, पुल जान ले रहे हैं, आग जान ले रही है, प्रदूषण जान ले रहा है, भ्रष्टाचार मार रहा है, उदासीनता मार रही है। भारत का शहरी स्तर पर पतन का कारण धन, प्रौद्योगिकी या समाधान की कमी नहीं है, बल्कि यह जवाबदेही के अभाव के कारण है।

घटना के बाद हरकत में आया प्राधिकरण

सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जीएनआईडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एन जी रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सड़कों पर या उसके आसपास के सभी गड्ढों की पहचान करें और उन्हें तुरंत भरें तथा दुर्घटना की आशंका वाले स्थानों को बिना किसी देरी के चिह्नित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि दिशासूचक चिह्न, रिफ्लेक्टर और अवरोधकों सहित आवश्यक सुरक्षा उपाय तीन दिनों के भीतर सभी सड़कों पर लागू किए जाएं।

अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद नपे कर्नाटक के डीजीपी

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी (सिविल राइट्स एनफोर्समेंट) को सस्पेंड कर दिया गया है। सोमवार (19 जनवरी) को उनका एक अश्लील वीडियो सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है।

वायरल वीडियो में डीजीपी के. रामचंद्र राव कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद सीएम सिद्धरमैया ने कहा था कि अगर अधिकारी दोषी पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी।

गृहमंत्री के घर से निकलने के बाद डीजीपी ने पत्रकारों से कहा था कि वीडियो झूठा और मॉर्फ्ड है। उन्होंने कहा कि आगे के एक्शन के बारे में वकील से बात करेंगे। राव ने अश्लील तरीके से काम किया है।

तमिलनाडु गवर्नर का बिना स्पीच दिए विधानसभा से वॉकआउट

कहा- राष्ट्रगान का फिर अपमान हुआ, सीएम स्टालिन बोले- ये असेंबली की बेइज्जती

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में फिर हाईलेवल ड्रामा हुआ। राज्यपाल आरएन रवि एक बार फिर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए स्पीच दिए बिना ही असेंबली से बाहर चले गए।

पिछले सालों की तरह गवर्नर ने कहा कि तमिल गान के बाद राष्ट्रगान बजाया जाए। लेकिन स्पीकर अप्पावु ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद गवर्नर रवि शुरुआती भाषण पढ़े बिना ही विधानसभा से बाहर चले गए। इससे पहले 2024-25 में भी वे ऐसा कर चुके हैं।राज्यपाल ने आरोप लगाया कि उनके भाषण में रुकावट डाली गई। उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं। राष्ट्रगान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। गवर्नर के वॉकआउट के बाद विपक्षी एआईएडीएमके के नेता भी असेंबली से बाहर चले गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं तमिलनाडु सीएम ने इसे असेंबली का अपमान बताया है।

लोक भवन बोला- गवर्नर का माइक बंद किया

राज्यपाल के असेंबली से बाहर जाने के बाद लोक भवन ने प्रेस रिलीज जारी की। रिलीज में कहा गया कि एक बार फिर राष्ट्रगान का अपमान किया गया। गवर्नर का माइक बार-बार बंद किया गया। उन्हें बोलने नहीं दिया गया।

ट्रम्प बोले- ग्रीनलैंड पर पीछे हटने का सवाल नहीं

यह दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी, ताकत के जरिए ही शांति कायम होगी

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ट्रम्प ने कहा कि ग्रीनलैंड राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ट्रम्प ने बताया कि इस मुद्दे पर नाटो चीफ मार्क रुटे से उनकी फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है।

केंद्र का बड़ा कदम- भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती

नईदिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने लोगों को गुमराह करने वाले झूठे और भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। खासकर कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के 'चमत्कारी इलाज' का दावा करने वाले प्रचार पर अब सीधे कार्रवाई की जाएगी। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने एक अहम अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत देश के 5 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों (एलजी) और प्रशासकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब ये

उपराज्यपालों को मिले विशेष अधिकार, अब होगी कार्रवाई

अधिकारी ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामलों में बिना देरी कार्रवाई कर सकेंगे।

नई व्यवस्था के तहत उपराज्यपाल और प्रशासक संदिग्ध संस्थानों की तलाशी ले सकेंगे, जरूरी दस्तावेज जब्त कर सकेंगे और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर वे गजेटेड अधिकारियों को भी जांच और कार्रवाई के अधिकार सौंप सकेंगे। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार यह व्यवस्था जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, और पुडुचेरी में लागू होगी। राष्ट्रपति के निर्देशों के तहत इन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक अब राज्य सरकार जैसी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएंगे।

यह कार्रवाई ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत की जाएगी।

कानपुर में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हंगामा

नाराज छात्रों ने कंप्यूटर-दरवाजे तोड़े, कहा- सर्वर फाल्ट नहीं, कोई धांधली हुई

कानपुर (एजेंसी)। कानपुर में मंगलवार को दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सर्वर फॉल्ट के चलते सुबह पहली शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ कर दी। सर्वर रूम में घुसकर छात्रों ने कंप्यूटर, कांच, दरवाजे, कुर्सियां, वायर तोड़ दिए। नाराज छात्रों ने बताया- पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से थी, जबकि एंट्री सुबह 8.45 बजे से होनी थी।

अन्य दो पाली की परीक्षा दूसरे कॉलेज में शिफ्ट की गई

एडीएम नरवल विवेक कुमार मिश्रा ने परीक्षा करा रही ईडिकुटी संस्था के सिटी हेड शुभम दीक्षित से बात की। शुभम दीक्षित ने बताया- मंगलवार को दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं होनी थी, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट होने से MGA कॉलेज में परीक्षा नहीं हो सकी। पहली शिफ्ट की परीक्षा को एसएससी द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसकी सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

यूपी में परिवार के 4 लोगों की हत्याकर जान दी

पत्नी, दो बेटे और मां के माथे पर गोली मारी

सहारनपुर (एजेंसी)। सहारनपुर में सरकारी अमीन ने पत्नी, दो बेटों और मां के माथे में गोली मारकर हत्या कर दी। फिर खुद के सीने और माथे पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपनी बहन को एक मैसेज और ऑडियो क्लिप भेजी। इसमें उसने कहा- वह परिवार की हत्या कर चुका है। अब खुद भी जान देने जा रहा है।

पति और पत्नी का शव फर्श पर, जबकि मां और दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े थे। अमीन के पास तीन तमंचे पड़े मिले। वारदात का पता उस वक्त चला।

राजस्थान में आंधी-बारिश की चेतावनी

विजिबिलिटी 50 मीटर से कम, यूपी के 10 शहरों में घना कोहरा

नई दिल्ली/ लखनऊ/ देहरादून (एजेंसी)। देश के उत्तरी इलाकों में मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के आने का अलर्ट है। यहां 5 दिन बाद आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल कई जिले कोहरे की चपेट में हैं, जिसके कारण विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। वहीं, उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में कोहरा छाया है। आगरा में ताज महल धुंध में छिप गया है। अगले 5 दिन तक यहां भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, बाराबंकी, हाथरस समेत 5 शहरों में बारिश हुई, जबकि अलीगढ़ और लखीमपुर खीरी में एक दिन पहले ओले भी गिरे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में नदी-नाले और झरने जम चुके हैं।

महाराष्ट्र में वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे पर प्राइवेट बस में आग लगी

मुंबई (एजेंसी)। मलाड इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मंगलवार सुबह एक प्राइवेट बस में आग लग गई। इससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

शहर के चार महत्वपूर्ण फ्लाईओवर का निर्माण जून तक पूरा करने के निर्देश

कलेक्टर ने किया अधिकारियों के साथ फ्लाईओवर का निरीक्षण

इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर में निर्माणाधीन चार प्रमुख फ्लाईओवरों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी फ्लाईओवर आगामी जून माह तक पूरे किए जाएं तथा निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, एसडीएम प्रदीप सोनी, अपर आयुक्त नगर निगम अभय राजनगांवकर सहित ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, प्रशासन, निर्माण एजेंसी एमपीआरडीसी और अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान देवास नाका, सत्य साईं चौराहा, मूसाखेड़ी, और क्रिस्टल आईटीआई पार्क चौराहा पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि ये सभी फ्लाईओवर शहर की यातायात व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके पूर्ण होने से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

बैठक में निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं, छोटे-छोटे रिमूवल (अतिक्रमण/संरचनाएं हटाने), वैकल्पिक व्यवस्थाओं और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने की रणनीति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि है। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के दौरान नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। ट्रैफिक संचालन के लिए गार्ड तैनात किए जाएं, ताकि यातायात सुचारु रहे। धूल उड़ने से रोकने के लिए नेटिंग और आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं। सर्विस लेन पर पैच रिपेयरिंग और डामरीकरण कर ट्रैफिक को सुचारू बनाया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य भले ही वर्तमान में समय-सीमा से पीछे चल रहा हो, लेकिन प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसे तेजी से पूरा करने के लिए प्रयासरत है। आने वाले दिनों में नियमित समीक्षा कर प्रगति की निगरानी की जाएगी।

कलेक्टर ने बताया कि चारों फ्लाईओवरों में मुख्य बाधाएं छोटी-छोटी रिमूवल और वैकल्पिक स्थान व्यवस्था से जुड़ी हैं। इन सभी बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं और जैसे ही ये बाधाएं हटेंगी, कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने मूसाखेड़ी चौराहा पार करने के लिए पैदल नागरिकों के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर के सर्विस रोड़ पर पर्याप्त लाईटिंग भी की जाए। कलेक्टर ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जून माह तक ये सभी फ्लाईओवर का निर्माण पूर्ण हों। निर्देश दिए गए है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, यह हमारी प्राथमिकता है। प्रशासन इंदौर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है।

बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर चूड़ियां उतरवाई

इंदौर। ई-रिक्शा में बैठकर जा रही महिला को अज्ञात बदमाशों ने झांसे में लेकर चूड़ियां उतरवा ली। घटना के बाद बदमाश रिक्शा से उतरकर भाग निकले। घटना रावजी बाजार थाना क्षेत्र की है। रिक्शा नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। चालक के पकड़ाने के बाद घटना का खुलासा हो सकेगा। पीड़िता साधना (65) निवासी चोइथराम मंडी ने बताया कि वह प्लास्टिक आयटम खरीदकर घर जाने के लिए रानीपुरा में खड़ी होकर ई रिक्शा का इंतजार कर रही थी। तभी ई-रिक्शा बुजुर्ग महिला के पास रुका और गंतव्य जाने का पूछा। महिला ने चोइथराम मंडी जाने की बात की। इस पर चालक ने 10 रुपए में चोइथराम मंडी तक छोड़ने का लालच दिया। रिक्शा में चार युवक और एक युवती पहले से सवार थे। महिला भी उनके साथ बैठ गई। संजय सेतु पर पहुंचने के बाद चालक ने आगे बैठे युवक को पीछे बैठने को कहा। कुछ देर बाद ई रिक्शा चालक ने रावजी बाजार थाना क्षेत्र में किसी काम का बहाना बनाकर महिला को उतार दिया और ई-रिक्शा लेकर फरार हो गया। बाद में महिला को पता चला कि उसकी सोने की चूड़ियां गायब है। महिला ने तत्काल घटना की सूचना परिजन और पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रकरण दर्ज किया। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस को आशंका है कि रिक्शा में पहले से बैठी सवारी ने वारदात को अंजाम दिया है। पूर्व से बैठी सवारी से रिक्शा चालक के संबंध हो सकते हैं।

सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ का शुभारंभ

इंदौर। सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ट्रैफिक डीसीपी आनंद कलादगी के निर्देशन में दो यातायात जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता रथ दंगल टीवी के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं, जो चारों प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों एवं भीड़भाड़ वाले मार्गों पर जाकर नागरिकों को सड़क सुरक्षा का संदेश देंगे। रथों में लगी डिजिटल स्क्रीन, फ्लैक्स, ऑडियो-विजुअल सिस्टम के माध्यम से यातायात नियमों से जुड़ी लघु फिल्में, वीडियो क्लिप और महत्वपूर्ण संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे। इस अवसर पर डीसीपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन कर हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे जागरूकता अभियानों से लोगों में नियमों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होगी। कार्यक्रम में दंगल टीवी के मालिक मनीष सिंघल, कंसल्टेंट रोहन झांझरिया, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात अधिकारी, ट्रैफिक प्रहरी एवं स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान चालकों को हेलमेट वितरित किए गए।

सब्जी विक्रेता पर चाकू से हमला

इंदौर। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में सब्जी का ठेला लगाने को लेकर हुए विवाद में दो युवकों ने सब्जी विक्रेता पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक शिवाजी नगर निवासी लक्की वर्मा मालवा मिल क्षेत्र में एमएल टावर के पास रोजाना सब्जी का ठेला लगाता है। शनिवार को ठेला लगाने के दौरान हेमंत तोमर और देवांश तोमर से जगह को लेकर विवाद हो गया। पहले गाली-गलौज हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। इसी दौरान देवांश ने चाकू निकालकर लक्की की कमर पर वार कर दिया। घायल लक्की मौके पर गिर पड़ा और शोर मचाने लगा। आसपास के लोगों के जमा होने पर आरोपी भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

सब्जी खरीद रहे युवक का मोबाइल चोरी

इंदौर। निरंजनपुर में सब्जी खरीद रहे युवक का मोबाइल अज्ञात बदमाश चुरा ले गया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर मंडी क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को महालक्ष्मी नगर स्थित स्पेस पार्क फेस-1 के निवासी जितेंद्र गौड़ ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। जितेंद्र शनिवार सुबह करीब 8.30 बजे निरंजनपुर सब्जी मंडी गए थे। उन्होंने अपना गोल्ड रंग का आईफोन पैंट की पिछली जेब में रखा था। मंडी में काफी भीड़ थी। सब्जी खरीदकर जब वे घर आने लगे तो मोबाइल चोरी होने का पता चला।

विधवा महिला के प्लॉट पर कब्जे का प्रयास

इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र में विधवा महिला के प्लाट को कथित बदमाश ने हड़पने की कोशिश की गई। बदमाश बाउंड्रीवाल से कूदकर अंदर गया और वहां स्टोर रुम को ध्वस्त कर सामान ले गया। लसूड़िया पुलिस को फिनिक्स टाउनशिप स्थित प्लॉट नंबर 409 और 410 की मालकिन कविता पंवार ने शिकायत करते हुए बताया कि वह विधवा है और लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही है। हाल ही में उनका पेट ऑपरेशन भी हुआ है। इस कारण वह अपने प्लॉट की नियमित देखरेख नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान उनके पड़ोसी राकेश विजयवर्गीय ने कब्जा करने की नीयत से प्लॉट की बाउंड्रीवाल गिरा दी। इतना ही नहीं, प्लॉट पर बने स्टोर रूम को भी पूरी तरह तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर जब पीड़िता मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने जबरन घुसपैठ कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। लसूड़िया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस कॉलोनी वासियों के बयान दर्ज कर रही है और चोरी गए सामान की जानकारी जुटाकर आरोपी की तलाश में लगी हुई है।

सनावद से लापता युवती की हादसे में मौत

इंदौर। सनावद से लापता हुई युवती की सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना सामने आने के बाद परिवार में मातम पसर गया है। मृतका अर्चना चौहान सुतारखेड़ा गांव जिला खंडवा की रहने वाली थी। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह अर्चना घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। परिजन उसे खोजते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में पता चला कि धनगांव के पास बाइक दुर्घटना में वह घायल हो गई थी। उसके साथ शुभम उर्फ शिवम नवल भी था, जिसका इलाज एमवाय अस्पताल में चल रहा है। अर्चना को पहले सनावद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से सोमवार सुबह इंदौर रेफर किया गया। एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। वहीं अर्चना के पिता भी जलगांव में काम करते हैं।

हर महीने थानों का मूल्यांकन होगा अच्छे कार्य पर पुरस्कार भी मिलेगा

पुलिस की कार्यप्रणाली सख्त होगी, पुलिस आयुक्त के निर्देश

इंदौर। शहर में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन को बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने सोमवार को अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण, आमजन की सुविधा, पुलिस की कार्यशैली में और अधिक कसावट लाने की कार्य योजना पर चर्चा की।

पुलिस आयुक्त ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि तैनात बल की उपस्थिति और कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। ड्यूटी ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, बीट-माइक्रो बीट स्टाफ और एफआरवी की सुनिश्चित की जाए। थानों में उपलब्ध संसाधनों की स्थिति की जांच हो। फरियादियों और आगंतुकों से संवेदनशील व्यवहार किया जाए। शिकायत मिलने पर अपराध पंजीकरण एवं कार्रवाई में किसी भी प्रकार की देरी न हो, चाहे मामला साइबर अपराध, ई-एफआईआर या जीरो एफआईआर से जुड़ा हो। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पर विशेष फोकस रखें। कोर्ट केसों की मॉनिटरिंग करें। कानून व्यवस्था से जुड़े आयोजनों और गतिविधियों पर नजर रखी जाए।

नई व्यवस्था लागू होगी- पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारियों के कार्यों के मूल्यांकन की नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक माह संबंधित जोन के डीसीपी और एडीसीपी द्वारा अपने क्षेत्र के 2 सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले थाने, 2 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले थाने चिह्नित किए जाएंगे। अच्छा कार्य करने पर थानों को प्रोत्साहन, खराब प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन बिंदुओं पर मूल्यांकन

थानों का मूल्यांकन महिला अपराधों पर कार्रवाई, संपत्ति अपराधों में रिकवरी, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी, समयबद्ध विवेचना, लंबित केसों का निराकरण, जमानत निरस्तीकरण, वारंट/समंस की तामिली, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, पासपोर्ट व चरित्र सत्यापन, पेट्रोलिंग, जनता से व्यवहार और सामुदायिक पुलिसिंग जैसे बिंदुओं पर किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने सभी एसीपी को न्यायालयीन कार्यों की नियमित समीक्षा के निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से जुड़े मामलों में 48 घंटे में और नोटिस 72 घंटे में जारी होना चाहिए।

ड्रग पार्टी के सनसनीखेज खुलासे जांच 'आंटी नेटवर्क' तक पहुंची

अबान शकील की गिरफ्तारी के बाद कई नए राज खुलेंगे

इंदौर। ड्रग पार्टी कांड में गिरफ्तार बिल्डर अबान शकील से पूछताछ के बाद चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कनाड़िया थाना पुलिस की कार्रवाई के बाद इस हाई-प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी रैकेट की परतें एक-एक कर खुलती जा रही हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से पहले रतलाम स्थित एक फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी की थी। पुलिस के अनुसार यह फार्म हाउस दानिश नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है, जहां नशे का खुला इस्तेमाल किया गया। पुलिस अब फार्म हाउस संचालक की तलाश में जुट गई है। अबान शकील की निशानदेही पर वैभव उर्फ बाबा और दो युवतियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके मोबाइल फोन से पार्टी के वीडियो बरामद हुए हैं। जांच के दौरान वैभव उर्फ बाबा के मोबाइल से 31 दिसंबर का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें इंदौर में आयोजित एक पार्टी के दौरान एमडी ड्रग के सेवन के सबूत सामने आए हैं। इस वीडियो में अबान शकील, वैभव उर्फ बाबा के साथ कई युवतियां भी नजर आ रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे मामले में अब तथाकथित 'आंटी नेटवर्क' की एंट्री भी सामने आई, जिससे नेटवर्क के और बड़े होने की आशंका जताई जा रही है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि कनाड़िया पुलिस पूरे ड्रग्स नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही और गिरफ्तारियां संभव हैं।

डिलीवरी बॉय ने मोबाइल नहीं दिया तो चाकू मारे और फरार

खजराना ब्रिज के पास रिंग रोड पर बदमाशों ने रोका

इंदौर। पलासिया इलाके में एक डिलीवरी बॉय के साथ लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। बदमाशों ने मोबाइल न देने पर युवक पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घायल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलासिया पुलिस के अनुसार घटना खजराना ब्रिज के पास रिंग रोड की है। यहां प्रमोद पुत्र चेतराम शाक्य, निवासी आईडीए मल्टी, जो एक निजी कंपनी में फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है, बाइक से जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक पीछे से आए और उसकी बाइक के आगे अपनी बाइक अड़ा दी। आरोपियों ने प्रमोद से मोबाइल फोन मांगा, लेकिन जब उसने मोबाइल देने से इंकार कर दिया और पुलिस को बुलाने की बात कही, तो एक आरोपी ने पीठ पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल प्रमोद को रात में उपचार के लिए पहले बॉम्बे अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बैंक अफसर का मोबाइल चोरी

इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक बैंक अफसर का सब्जी मंडी से मोबाइल चोरी हो गया। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र गोड निवासी स्पेश पार्क ने शिकायत दर्ज कराई है। जितेंद्र बैंक में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि वे निरंजनपुर स्थित सब्जी मंडी सब्जी खरीदने गए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात आरोपी ने मौका पाकर उनकी जेब से आईफोन मोबाइल चोरी कर लिया।

दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी के आरोपी अभी तक नहीं पकड़ाए

पुलिस कार्रवाई से नाराज समाज ने निकाली शांतिपूर्ण रैली

इंदौर। पाटनीपुरा क्षेत्र स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मकर संक्रांति की रात चोरी हो गई थी। घटना के आरोपियों को पकड़ने जैन समाज ने एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। चोरी की वारदात को दो पुरुष और महिला ने अंजाम दिया था। घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें बदमाश भागने में जिस बाइक का उपयोग करते हैं, वह भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यह पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध कराई जा चुकी है, लेकिन घटना के पांच दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इससे समाजजन एवं क्षेत्रीय व्यापारियों में असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है। पुलिस कार्रवाई से नाराज समाज ने पाटनीपुरा से एमआईजी थाने तक शांतिपूर्ण रैली निकाली। समाज के विकास जैन सतभैया ने बताया कि इसी के विरोध में सोमवार को पाटनीपुरा जैन मंदिर से रैली निकाली गई। रैली में समाजजन णमोकार मंत्र का जाप करते हुए थाने पहुंचे और टीआई को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई।

बाप ने सरिया बेचकर शराब पी तो नाराज बेटे ने हत्या कर दी

बीमारी के बहाने से अस्पताल ले गए आरोपी गिरफ्तार

इंदौर। खुद के मकान निर्माण के सरिए बेचकर पिता ने शराब पी ली। जब बेटे को यह पता चला तो वह नाराज हो गया। उसने पिता के इस कृत्य का विरोध किया। पिता ने भी बेटे से विवाद किया। विवाद के चलते बेटे ने डंडे और पाइप से पिता को जमकर पीटा। अचेत होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद बुजुर्ग पिता ने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। लसूड़िया थाना प्रभारी तारेश सोनी के मुताबिक, घटना 13 जनवरी को स्कीम नंबर 78 में हुई थी। यहां रहने वाले संजय पिता जगन्नाथ गोलाई (55) का मकान बन रहा है।

मकान का निर्माण उसका ठेकेदार बेटा राहुल (26) कर रहा है। संजय शराब पीने का आदी है। उसने पत्नी से शराब के पैसे मांगे थे। जब पत्नी ने पैसे नहीं दिए तो वहां पड़ा सरिया निकालकर बेच दिया। जब बेटे को सरिया चोरी का पता चला तो उसने पिता से बात करना चाही। इसी विवाद के दौरान राहुल ने अपने पिता के साथ मारपीट की, जिससे संजय की हालत बिगड़ गई।

तबीयत खराब बताकर भर्ती कराया

परिजनों ने मारपीट की जानकारी पुलिस को नहीं दी और तबीयत खराब होना बताकर संजय को अस्पताल में भर्ती कराया। एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार 18 जनवरी को उसकी (संजय) मौत हो गई। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि जब संजय को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, तब वे गिरने से चोट लगने की बात कह रहे थे। फिलहाल मामला जांच में है और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

तंबाकू के लिए सरिए बेचे

इधर, संजय (मृतक) की बहन निर्मला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके भतीजे राहुल को तंबाकू लाने के लिए पैसे चाहिए थे। इसी बात को लेकर उसने सरिए बेच दिए थे। जब संजय ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई।

गूगल में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, 20 लाख की ठगी हुई

तीन अलग-अलग मामलों में बदमाशों ने ऑनलाइन ठगी की

इंदौर। शहर में पिछले दिनों तीन अलग-अलग तरीके से बदमाशों ने ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। इन वारदातों से 20 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़प ली। छोटा बांगड़दा क्षेत्र में रहने वाले दो सगे भाइयों के साथ आईटी दिग्गज 'गूगल' में उच्च पदों पर नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए ठग लिए। बताया गया कि जालसाजों ने बाकायदा फर्जी इंटरव्यू लेटर, जॉइनिंग लेटर और कंपनी एग्रीमेंट तक तैयार कर पीड़ितों को भेजे थे। मामले में पटियाला निवासी मुख्य आरोपी और उसके साथियों पर पुलिस ने केस दर्ज है। स्मृति नगर निवासी फरियादी आयुष का वर्ष 2019 में उसका संपर्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पंजाब के ऋषभ कुमरावत से संपर्क हुआ था। ऋषभ ने वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनवाए और समय पर भुगतान कर उसका भरोसा जीत लिया। इसके बाद ऋषभ ने दावा किया कि वह गूगल कंपनी के एंटीवायरस विभाग में सीनियर जोनल हेड अमितोष भट्टाचार्य के साथ काम करता है। उसने मुझे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर और उसके भाई पीयूष को हंगरी (यूरोप) में सीनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी का लालच दिया। 2022-23 के बीच आरोपियों ने प्रोसेसिंग फीस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इंग्लिश सर्टिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस, जॉइनिंग बांड और एम्बेसी फीस जैसे अलग-अलग बहाने बनाकर आयुष और पीयूष से किस्तों में रुपए वसूल लिए।

रिफंड के नाम पर टालमटोल

जब तय समय सीमा बीतने के बाद भी इंटरव्यू नहीं हुआ और जॉइनिंग की तारीखें आगे बढ़ती रहीं तो पीड़ितों को शंका हुई। दबाव बनाने पर आरोपियों ने रिफंड का झांसा दिया और मार्च 2024 तक पैसे लौटाने का वादा किया। तय समय बीतने के बाद जब आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया, तब आयुष ने शिकायत दर्ज कराई।

नौकरी के नाम पर डेढ़ लाख ठगे

क्षिप्रा थाना क्षेत्र में शातिर जालसाजों ने युवक को प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी दिलाने का लालच देकर उससे डेढ़ लाख रुपए ऐंठ लिए। ठगी का शिकार होने के बाद जब युवक को न तो नौकरी मिली और न उसके पैसे वापस आए, तब उसने पुलिस की शरण ली। रामेश्वर धाम कॉलोनी के निवासी प्रतीक बोडाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि यह घटना 19 दिसंबर को शुरू हुई थी। प्रतीक के मुताबिक, आरोपी सीता कुमार और अदिति ने उससे ऑनलाइन माध्यम से संपर्क किया था। उन्होंने खुद को जॉब कंसल्टेंट या कंपनी प्रतिनिधि बताते हुए उसे नामी कंपनी में अच्छे पद और वेतन पर काम दिलाने का प्रलोभन दिया।

आर्मी अफसर बताते हुए धोखा

तुकोगंज थाना क्षेत्र में जालसाजों ने खुद को आर्मी अधिकारी बताकर घरेलू सामान का आर्डर दिया और फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर युवक से 4 लाख रुपए ऐंठ लिए। तुकोगंज पुलिस के मुताबिक, नरीमन सिटी छोटा बांगड़दा निवासी विशाल रघुवंशी की कंपनी का साउथ तुकोगंज स्थित ट्रेड सेंटर में ऑफिस है। घटना 6 दिसंबर की है। जब कंपनी के सेल्समैन तरुण भदौरिया के पास दो अलग-अलग नंबरों से फोन आए। जालसाजों ने विश्वास जीतने के लिए कंपनी से ही 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' करवा लिए। जब कंपनी ने सामान तैयार कर गाड़ी लोड करने के लिए आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके मोबाइल नंबर मिले।

संपादकीय

नबीन के सामने चुनौतियां

युवा नेता व भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का भाजपा का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना जाना केवल एक वैधानिक औपचारिकता थी। नबीन का चयन चूंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है, इसलिए उसे चुनौती मिलने का सवाल ही नहीं था। वे स्वयं नबीन के प्रस्तावको में थे। कहा जा रहा है कि नबीन संघ की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन अगर वो आरएसएस के एजेंडे को ठीक से आगे बढ़ाते रहे तो संघ भी उन पर अपनी मोहर लगा देगा। हालांकि नितिन नबीन की पृष्ठभूमि आरएसएस वाली नहीं रही है। इन्होंने पढ़ाई भी सेंट माइकल हाई स्कूल पटना से और दिल्ली के कर्नल सत्संगी किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल से इंटमीडिएट की पढ़ाई की है। नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव ज़रूर रहे हैं। वैसे 2014 के बाद की बीजेपी में यह खास मायने नहीं रखता कि किस की क्या पृष्ठभूमि है। पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। चूंकि यह कई विधानसभाओं के चुनाव का वर्ष है और उनके पूर्ववर्ती अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने चुनावी सफलताओं की लंबी लकीर खींच रखी है, इसलिए नबीन को अपने चयन के औचित्य को साबित करना होगा। नड्डा ने जहां पार्टी को छोड़ा है, उसके आगे ले जाना होगा। दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय में आयोजित बधाई समारोह में पीएम मोदी ने नबीन को मिलेनियल जनरेशन का प्रतिनिधि बताया और कहा कि वो संगठन, सरकार में काम करने वाला तथा टेक फ्रेंडली होने से पार्टी की नई पीढ़ी से सीधा कनेक्ट बना सकेंगे। वैसे भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चलने वाले नामों को दरकिनार कर अल्पज्ञात नितिन नबीन को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान सौंपना सभी के लिए चौंकाने वाला था। लेकिन लगता है कि मोदी शाह को नबीन की क्षमताओं पर भरोसा है, इसीलिए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि भाजपा में युवा हाथों में नेतृत्व सौंपने की परंपरा नई नहीं है। अटलजी भी जब पहली बार तत्कालीन जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, तब वो 44 साल के यानी नबीन से भी एक साल छोटे थे। अपनी प्रतिभा और वक्तृत्व क्षमता से वो जल्द ही राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गए। नबीन के व्यक्तित्व में क्या खूबियां हैं, यह आने वाले समय में पता चलेगा। जानकारों का कहना है कि भाजपा में अध्यक्ष कोई भी बने, उसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती। उसे मोदी और शाह के बताए रास्ते पर चलना होता है। नबीन कितनी कुशलता से यह काम कर पाते हैं, उसी आधार पर उनकी मार्किंग होगी। नए अध्यक्ष के रूप में नबीन को हनीमून पीरियड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जल्द ही बंगाल सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। नबीन के नेतृत्व और संगठन क्षमता की पहली अग्नि परीक्षा तो उस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में होगी, जो नबीन के गृह राज्य से लगा है और जहां ममता बैनजी से 15 साल से अंगद के पांव की तरह डटी हैं। अगर नबीन के नेतृत्व में भाजपा बंगाल में चुनाव जीत पाती है तो यह नया इतिहास रचने जैसा होगा। इसके अलावा असम और पुडुचेरी में भाजपा की सत्ता में वापसी और तमिलनाडु और केरल में भाजपा की ताकत बढ़ाने की चुनौती नबीन के सामने होगी। इससे भी बड़ी चुनौती नबीन के सामने पार्टी को 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयार करने की होगी। ये ऐसे समय में होंगे, जब देश परिसीमन की प्रक्रिया से गुज़र रहा होगा। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण लागू किया जा रहा होगा। ऐसे में नए अध्यक्ष को बदले हुए राजनीतिक माहौल के अनुरूप पार्टी को तैयार करना होगा।

ईरान संकट : भारत के लिए स्थिरता ही रणनीति

नजरिया
अंशुमान
लेखक संसद टीवी से जुड़े पत्रकार हैं।

ईरान में हालिया घटनाक्रम सिर्फ ईरान की आंतरिक उथल-पुथल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक निहितार्थ हैं। पश्चिम एशिया के इस महत्वपूर्ण देश में बढ़ता जन असंतोष, आर्थिक संकट और वैश्विक तनाव ऐसे समय सामने आए हैं, जब वैश्विक व्यवस्था पहले ही अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। यह स्थिति भारत के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ईरान न केवल उसकी ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि मध्य एशिया, अफगानिस्तान और यूरेशिया तक उसकी रणनीतिक पहुँच का भी एक प्रमुख रास्ता भी है।

ईरान में मौजूदा असंतोष की जड़ें बेहद गहरी हैं। दशकों से लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने ना सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है बल्कि महंगाई, बेरोज़गारी, मुद्रा अवमूल्यन और जीवन-यापन की बढ़ती लागत ने आम नागरिक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की सरकार ने आर्थिक हालात की गंभीरता को स्वीकार भी किया है, लेकिन सुधारों की गति और प्रभाव को लेकर जनता में निराशा बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह असंतोष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है, जिसे युवा और शिक्षित आबादी खुलकर व्यक्त कर रही है।

इसमें कोई संदेह नही है कि आंतरिक कारणों के साथ-साथ बाहरी दबावों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की ईरान को लेकर रणनीति लंबे समय से दबाव, प्रतिबंध और अलगाव पर आधारित रही है। हालिया प्रदर्शनों के दौरान पूरे विश्व ने देखा कि पश्चिमी नेताओं के बयान और खुले समर्थन ने ईरान के भीतर यह धारणा और मजबूत की है कि इन आंदोलनों को बाहरी ताक़तें अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। पूर्व में हम लीबिया, इराक और सीरिया जैसे उदाहरण देखें तो हमें यह समझने में आसानी होगी कि ईरान और पूरे क्षेत्र के लिए यह एक चेतावनी हैं कि शासन परिवर्तन के नाम पर किया गया विदेशी हस्तक्षेप अक्सर दीर्घकालिक अस्थिरता ही लेकर आता है।

भारत इस संदर्भ में एक अलग और संतुलित दृष्टिकोण रखता है। भारत ने परंपरागत रूप से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से परहेज़ किया है और संवाद व कूटनीति को प्राथमिकता दी है। यह नीति भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह पश्चिम एशिया में किसी एक ध्रुव के साथ खड़े होने के बजाय सभी प्रमुख पक्षों से संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। भारत के लिए ईरान की स्थिरता कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, ऊर्जा सुरक्षा। भले ही हाल के वर्षों में भारत ने ईरान से तेल आयात कम किया हो, लेकिन पश्चिम एशिया में किसी भी बड़े टकराव का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाज़ार पर पड़ेगा। होर्मुज़ जलडमरूमध्य में अस्थिरता तेल और गैस की कीमतों को प्रभावित कर सकती है, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। दूसरा, समुद्री व्यापार और आपूर्ति शृंखला। भारत का एक बड़ा व्यापार पश्चिम एशिया और यूरोप से होकर गुजरता है। लाल सागर, फारस की खाड़ी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में किसी भी तरह का सैन्य टकराव वैश्विक समुद्री व्यापार को बाधित कर सकता है। हालिया वर्षों में वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की नाजुकता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सबक रही है। तीसरा, रणनीतिक संपर्क और क्षेत्रीय पहुँच। ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए केवल एक व्यापारिक परियोजना नहीं है, बल्कि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच का एक अहम माध्यम है। अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) भारत, ईरान, रूस और मध्य एशिया को जोड़ने वाली एक दीर्घकालिक रणनीतिक परियोजना है। यदि ईरान में अस्थिरता बढ़ती है या उस पर नए और कठोर प्रतिबंध लगते हैं, तो इन परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो सकती है।

भारत-ईरान संबंधों में जो सबसे खास बात यह रही है कि दोनों देशों ने कठिन परिस्थितियों में भी संवाद बनाए रखा है। अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट जैसे कानूनों और प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ईरान के साथ संपर्क पूरी तरह समाप्त नहीं किया। चाबहार परियोजना को प्रतिबंधों से मिली अस्थायी छूट इसी संतुलित कूटनीति का परिणाम है। वर्तमान संकट में भारत की भूमिका केवल एक दर्शक की नहीं हो सकती। इन सभी घटनाक्रम में भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से यह संकेत दिया है कि वह क्षेत्र में तनाव कम करने और संवाद को बढ़ावा देने के पक्ष में है। विदेश मंत्री द्वारा ईरान और अमेरिका दोनों से संपर्क बनाए रखना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के साथ एक रणनीतिक स्वायत्तता का संदेश भी है कि भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में आए बिना अपने हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है।

हालाँकि इन सभी घटनाक्रम में भारत को इस संतुलन में सावधानी भी बरतनी होगी क्योंकि एक ओर अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भारत के गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ उसके ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक हित जुड़े हैं। किसी भी पक्ष के साथ अत्यधिक झुकाव भारत की दीर्घकालिक रणनीति के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए भारत के लिए सबसे विवेकपूर्ण रास्ता यही है कि वह तनाव कम करने, प्रतिबंधों में यथासंभव छूट लाने और रीजनल डॉयलॉग को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करे।

इस संदर्भ में भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय कार्यरत हैं, जिनकी आजीविका और सुरक्षा सीधे तौर पर क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी हुई है। ईरान में किसी भी बड़े पैमाने की अस्थिरता या सैन्य टकराव का प्रभाव आसपास के देशों तक फैल सकता है। हाल के वर्षों में भारत ने संकटग्रस्त क्षेत्रों से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की क्षमता का प्रदर्शन किया है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान केवल स्थिरता और शांति से ही संभव है। ईरान के आंतरिक हालात पर भारत का रुख भी संतुलित होना चाहिए। जनता की वैध आर्थिक और सामाजिक आकांक्षाओं को समझते हुए भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि किसी भी देश की स्थिरता उसके अपने लोगों द्वारा तय की जानी चाहिए, न कि बाहरी हस्तक्षेप से। दमन और हिंसा से अस्थायी शांति तो मिल सकती है, लेकिन स्थायी समाधान केवल समावेशी सुधारों और संवाद से ही संभव है।

चाबहार परियोजना भी इस दृष्टि से एक परीक्षा भी है और अवसर भी, क्योंकि यह बंदरगाह न केवल भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक यूरेशियन रणनीति का आधार भी है। यदि ईरान पर प्रतिबंधों का दायरा और बढ़ता है या वहां अस्थिरता गहराती है, तो इस परियोजना की गति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में भारत को वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी विचार करना होगा, लेकिन चाबहार की केंद्रीयता को कम किए बिना। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत यह भलीं भांति समझता है कि ईरान में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहने की स्थिति में चीन और रूस की भूमिका और मजबूत हो सकती है। पहले से ही चीन ने ईरान के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक समझौते किए हैं। यदि भारत इस क्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता या निष्क्रियता दिखाता है, तो उसके लिए भविष्य में रणनीतिक स्पेस सीमित हो सकता है। इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह ईरान के साथ अपने संपर्कों को केवल प्रतीकात्मक न रखे, बल्कि आर्थिक, कनेक्टिविटी और कूटनीतिक स्तर पर उन्हें सार्थक बनाए।

मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में जब यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट और एशिया प्रशांत में बढ़ते तनाव विश्व व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, ईरान में किसी भी बड़े टकराव का असर किसी भी सीमा तक जा सकता है। भारत जैसे उभरते वैश्विक शक्ति के लिए यह एक कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी है जहाँ उसे अपने राष्ट्रीय हितों, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के बीच संतुलन साधना होगा। अंततः, ईरान का भविष्य उसके अपने लोगों और नेतृत्व के निर्णयों पर निर्भर करेगा। लेकिन भारत के लिए यह स्पष्ट है कि एक स्थिर, शांत और संवाद आधारित ईरान ही उसके हित में है। टकराव, प्रतिबंध और हस्तक्षेप की राजनीति से दूर रहकर कूटनीति, संपर्क और सहयोग का रास्ता ही न केवल ईरान, बल्कि पूरे क्षेत्र और भारत के लिए भी बेहतर भविष्य की नींव रख सकता है।

हिन्दुओं के मानवाधिकारों पर वैश्विक चुप्पी

मुद्दा
डॉ. लोकेन्द्र सिंह
लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।

गरिमामयी जीवन जीने के लिए मनुष्य होने के नाते हमारे कुछ अधिकार हैं। वैश्विक स्तर पर मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा हो सके, इस उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर, 1948 को 'मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा' की। यह दस्तावेज मानव जीवन, स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को परिभाषित करता है। भारत के संविधान में भी कई अनुच्छेद मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मानवाधिकारों का हनन रोकने, उनकी निगरानी करने एवं इससे जुड़े अन्य मामलों पर हस्तक्षेप करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएँ भी गठित की गई हैं। परंतु, विडंबना यह है कि इन संस्थाओं को अन्य समुदायों के मानवाधिकारों की चिंता तो होती है, लेकिन हिंदुओं के मानवाधिकार इन्हें संभवतः दिखाई ही नहीं देते। विश्व के विभिन्न देशों में हिंदुओं के मानवाधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है, लेकिन कहीं कोई घोर आपत्ति सुनाई नहीं देती। एक प्रकार से वैश्विक चुप्पी छाई हुई है। यह स्थिति चिंताजनक है। यह चुप्पी हिंदू समाज के मन में आक्रोश पैदा करती है और सांप्रदायिक भेद भी बढ़ाती है।

दुनिया के कई देशों में जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और जीवन के मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत के पड़ोसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में स्थिति बहुत चिंताजनक है। इन देशों में इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों ने प्रारंभ से ही हिंदुओं को अपने निशाने पर लिया है, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ हिंदुओं की संख्या में तेजी से कमी आई है। हिंदुओं की बड़ी संख्या का धर्मांतरण करा लिया गया है या फिर उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है।

बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से हिंदुओं पर हमलों के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। तख्तापलट के बाद वहाँ कट्टरपंथी समूह सत्ता के करीब आ गए हैं, जिसके कारण अतिवादी ताकतों ने हिंदुओं पर हमले तेज कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, संपत्ति और मंदिरों पर व्यापक हमले, तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। इस्कॉन मंदिर जैसी पवित्र जगहों को भी निशाना बनाकर आग लगा दी गई। कट्टरपंथी समूहों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जानबूझकर देशद्रोह और हिंसक प्रदर्शन जैसे गंभीर मामलों के फर्जी केस दर्ज करवाए जाते हैं, ताकि उन्हें कानूनी उलझनों में फंसाया जा सके।

चूँकि भारत में हिंदुओं के हितों की चिंता करने वाली केंद्र सरकार है, इसलिए सरकार ने बांग्लादेश के हालात पर तत्काल संज्ञान लेकर वहाँ की सरकार पर दबाव बनाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक हिंसा की 2400 से अधिक घटनाएँ दर्ज हुई हैं। भारत ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच करेगा और हत्या, आगजनी व हिंसा के सभी दोषियों को सजा देगा। हालांकि, इसकी उम्मीद कम ही है कि बांग्लादेशी प्रशासन हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा।

इसी प्रकार, पाकिस्तान में भी हिंदू समुदाय प्रारंभ से ही उत्पीड़न का सामना कर रहा है। वहाँ की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, सांप्रदायिक ताकतों और सेना के बढ़ते प्रभुत्व के बीच तथाकथित लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर हो गई हैं। पाकिस्तान में हिंदू और अन्य गैर-इस्लामिक समुदायों की युवतियों और लड़कियों का जबरन धर्मांतरण, अपहरण, तस्करी और बाल विवाह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। विडंबना यह है कि पुलिस अक्सर अपहरण के मामलों को 'प्रेम विवाह' बताकर खारिज कर देती है। अदालतों द्वारा भी जबरन विवाह को अक्सर धार्मिक कानूनों का सहारा लेकर वैध करार दिया जाता है। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों का उपयोग हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए किया जाता है; भीड़ महज आरोप के आधार पर हत्या कर देती है और दोषियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती।

मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को स्वाभिमान से जीवन देने के लिए 'नागरिकता संशोधन कानून' लागू किया था, लेकिन भारत के तथाकथित प्रगतिशील मानवतावादियों को ही यह पहल चुभ गई। रोहिंग्या जैसे समुदायों की अवैध घुसपैठ के लिए विलाप करने वाले इन 'सेकुलर' धुरंधरों को हिंदुओं के मानवाधिकारों की चिंता नहीं है। यह साबित करता है कि वैश्विक स्तर पर ही नहीं, बल्कि भारत में भी कई ऐसे समूह हैं जो हिंदुओं के मानवाधिकारों की जानबूझकर अनदेखी करते हैं।

पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक हिंदुओं के उत्पीड़न पर तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग और संस्थाएँ चुप्पी साधे रहती हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जाँच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आयोग ने स्पष्ट कहा कि राज्य में 'कानून का शासन नहीं, बल्कि शासक का कानून चल रहा है'। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या हिंदुओं के कोई मानवाधिकार नहीं हैं? उनकी चिंता कौन करेगा?

हमें स्मरण रखना चाहिए कि मानवाधिकारों का संरक्षण एक सार्वभौमिक प्रतिबद्धता है। अन्य समाजों की तरह ही हिंदू समुदाय को भी भय और उत्पीड़न से मुक्त जीवन जीने की गारंटी मिलनी चाहिए। यह केवल संबंधित सरकारों की ही नहीं, बल्कि वैश्विक बौद्धिक समुदाय का भी नैतिक दायित्व है कि मानवाधिकारों के सिद्धांतों को हर जगह निष्पक्षता से लागू किया जाए। जहाँ भी हिंदुओं के मानवाधिकारों का हनन हो, वहाँ भी उनके पक्ष में आवाज बुलंद की जानी चाहिए ताकि वैश्विक संस्थाओं पर दबाव बने। याद रहे कि 'मानवाधिकार कोई चुनिंदा अधिकार नहीं हैं जिन्हें सुविधानुसार लागू किया जाए; यदि ये 'सार्वभौमिक' हैं, तो इनमें हिंदू समाज की पीड़ा को भी समान स्थान मिलना चाहिए'।

धारा 17 ए: संरक्षण या समानता?

कानून और न्याय
डॉ. भूपेंद्र कुमार सुल्लेरे

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष और कानून की सीमाएँ भारत में भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक नैतिकता, लोकतांत्रिक जवाबदेही और नागरिक विश्वास से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए समय-समय पर अनेक कानून बनाए गए, संस्थागत ढाँचे खड़े किए गए, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह बार-बार देखा गया कि कानून की पहुँच नौकरशाही और सत्ता के उच्चतम स्तर तक समान रूप से नहीं हो पाती। पिछले लगभग तीन दशकों में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न बार-बार आया है कि क्या कुछ विशेष पदों पर बैठे लोक सेवकों को जांच से पहले 'पूर्व स्वीकृति' की आवश्यकता वास्तव में ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करती है, या यह भ्रष्ट अधिकारियों के चारों ओर एक कानूनी दीवार खड़ी कर देती है। इस संदर्भ में तीन प्रमुख न्यायिक पड़ाव रहे हैं–विनीत नारायण मामला (1997), डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी मामला (2014) और 13 जनवरी 2026 को सीपीआईएल से संबंधित निर्णय।

इन तीनों मामलों को जोड़ने वाला साझा सूत्र है 'पूर्व स्वीकृति' के विरुद्ध चला संवैधानिक संघर्ष। विनीत नारायण मामला (1997) : 'एकल निर्देश' और कानून के समक्ष समानता विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामला, जिसे सामान्यतः जैन हवाला कांड के नाम से जाना जाता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध न्यायिक हस्तक्षेप का ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया तथाकथित 'एकल निर्देश' चुनौती के रूप में आया। इस निर्देश के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो को केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों, साथ ही आरबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की जांच करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था। जैन हवाला कांड में गुप्त डायरियों के माध्यम से शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों को कथित भुगतान का खुलासा हुआ था, जिसने पूरे तंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस 'एकल निर्देश' को रद्द करते हुए कहा कि यह सीबीआई के वैधानिक अधिकारों में अवैध हस्तक्षेप है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिकारियों का ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बनाना, जिन्हें जांच से छूट मिले, जबकि कनिष्ठ अधिकारी उसी आरोप में जांच के दायरे में आएँ, संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। कार्यपालिका किसी निर्देश के माध्यम से कानून के संचालन को नहीं रोक सकती। इस फैसले ने यह स्थापित किया कि कानून के समक्ष पद या ओहदा कोई सुरक्षा कवच नहीं हो सकता।

धारा 6ए : रद्द किए गए निर्देश की वैधानिक वापसी विनीत नारायण फैसले के बाद सरकार ने 2003 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में धारा 6ए जोड़ दी। यह धारा वही व्यवस्था कानून के रूप में वापस लाई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय पहले ही अस्वीकार कर चुका था। इसके तहत संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की जांच के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने इस धारा को यह कहते हुए चुनौती दी कि यह रद्द किए गए एकल निर्देश का ही पुनरुत्थान है। उनका तर्क था कि इससे न केवल नियमित जांच, बल्कि प्रारंभिक जांच भी बाधित होती है, जिससे भ्रष्टाचार की शिकायतों की सच्चाई सामने आने से पहले ही मामला समाप्त हो जाता है। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने धारा 6ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह पद के आधार पर अवैध वर्गीकरण करती है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह फैसला सरकार के लिए बड़ा झटका था, विशेषकर उस दौर में जब यह कहा जा रहा था कि वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार जांच के डर से नीतिगत निर्णय लेने से हिचक रहे हैं। धारा 17ए और 'नीतिगत गतिरोध' का तर्क धारा 6ए के निरस्त होने के बाद सरकार ने यह तर्क आगे बढ़ाया कि बिना किसी सुरक्षा के ईमानदार अधिकारी साहसिक निर्णय लेने से डरने लगेंगे, जिससे शासन और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसी तर्क के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के माध्यम से धारा 17ए लाई गई। धारा 17ए के अनुसार, किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की पूछताछ या जांच से पहले संबंधित सरकारी प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। सरकार ने इसे पद-निरपेक्ष बताया और कहा कि यह सभी लोक सेवकों पर समान रूप से लागू होती है, इसलिए यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती।

इसके विपरीत, न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने धारा 17ए को संवैधानिक रूप से वैध माना। उन्होंने कहा कि केवल दुरुपयोग की आशंका के आधार पर पूरे कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया के दौर में किसी ईमानदार अधिकारी पर जांच मात्र से उसकी साख को अपूरणीय क्षति हो सकती है। उन्होंने समाधान के रूप में सुझाव दिया कि पूर्व स्वीकृति का निर्णय सरकार के बजाय लोकपाल या लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाए और उनकी सिफारिश बाध्यकारी हो। आंकड़े, वास्तविकता और बढ़ती चिंता भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामे से स्थिति और भी चिंताजनक दिखाई देती है। 2018 के बाद सीबीआई द्वारा धारा 17ए के तहत मांगी गई 2,395 पूर्व स्वीकृतियों में से 41.3 प्रतिशत मामलों में अनुमति से इनकार कर दिया गया। बड़ी संख्या में मामले वर्षों तक लंबित रहे, जबकि कानून में तीन से चार महीने की समय-सीमा निर्धारित है। इन देरीयों के कारण अनेक मामलों में जांच प्रभावी रूप से शुरू ही नहीं हो पाई।

संरक्षण या जवाबदेही विनीत नारायण से लेकर सीपीआईएल तक सर्वोच्च न्यायालय का पूरा विमर्श एक मूल प्रश्न पर केंद्रित रहा है–क्या पूर्व स्वीकृति व्यवस्था ईमानदार प्रशासन की रक्षा का साधन है या भ्रष्टाचार को संस्थागत संरक्षण देने का तरीका। अब यह प्रश्न एक बड़ी पीठ के समक्ष निर्णीत होना शेष है। तब तक धारा 17ए लागू रहेगी और कानूनी अनिश्चितता बनी रहेगी। न्याय में देरी का लाभ व्यवस्था को मिल सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जनता के विश्वास को होता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में कानून की धार कुंद नहीं होनी चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र का आधार ही कमजोर पड़ जाएगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

जल से जलजला और पानी से जले लोग

व्यंग्य
प्रीतम लखवाल
लेखक व्यंग्यकार हैं।

मौसम बेईमान सा हो रहा था। शीतलहर अपना प्रभुत्व कायम कर चुकी थी। इसका प्रभाव ठीक वैसा ही देखने में आया जैसा एक नेता का अपने क्षेत्र की जनता के बीच होता है। शीतलहर के आने का कोई समय निश्चित नहीं होता, उसी तरह हमारे नेताजी का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब आना होता है, आ जाते हैं। उनका तूफानी दौरा तो शीतलहर या लू चलने के समय नहीं चुनाव की लू-लपट के बीच अधिक होता है। इस दौरान उन्हें यह डर सता रहा होता है कि कहीं उनके वोट बैंक में कहीं कोई शार्ट सर्किट न हो जाए। खैर, विगत दिनों शीतलहर में हमारे शहर का एक खास कथित गरीब मोहल्ला इतना गर्मा रहा है कि पूछो ई मत। पूरी दुनिया को पता लग गया कि पानी की अहमियत क्या है? लोग इसमें भी विज्ञान की बातें करने लगे हैं। पानी का क्या मोल है? पानी क्यों जरूरी है? धरती पर जितने प्रतिशत पानी मौजूद है, उतना ही हमारे शरीर में मौजूद है। एक ओर विगत दिनों लोग शीतलहर से ठिठुर रहे थे तो नेताजी का दिमाग एकदम से भट्टी हो रिया था। कहना क्या चाह रहे थे और निकल कुछ और रिया था भिया। खैर, नेता होने के साथ-साथ वे मंत्री भी हैं। इससे उनके कद, पद के वजन का अंदाजा लगाकर ही उनसे सवाल किए जाने चाहिए। अब देखिए न उनके ही राज में, उनके ही शहर में, उनके ही विभाग के अफसर भी सारे मूक बघिर हैं। नेता बनाम मंत्री शिकायत करते फिर रहे हैं कि अफसर उनकी नहीं सुन रहे। अब उनको कौन बताए कि उन्होंने अफसर ही ऐसे भर्ती कर रखे हैं, जो मूक बघिर हैं। जिनमें न सुनने की क्षमता है न बोलने की। बस उनकी मुंडी ही हिलती है। वह भी तब जब कोई योजना को मंजूरी देना होती है या किसी की फाइल को कचरा पात्र में फेंकना होता है तब। उनकी मुंडी तो कभी हां में तो कभी ना में हिलती देखी है। उनकी आंखें तो केवल तब चमकती हैं, जब करोड़ों का पैकेज योजना-परियोजना की बुलेट ट्रेन पर सवार होकर आता है। वे अच्छा भला रोड खोदकर दुबारा बनाने का टैंडर पास कर देते हैं। बस, उनको 40 साल से सड़ी नल की पाइप लाइन नहीं दिखती। बताते हैं कि उनकी आंखों में मोतियाबिंद का असर होने लगा है। पाइप भी इतनी बेशर्म है कि जो फूटकर मल-मूत्र वाहक बनकर लोगों की जिंदगी को छोटी करने पर तुल रही है और अफसर हैं कि अपने ऑफिस में शीतलहर में हीटर लगाकर रिवाल्विंग चेयर पर मस्ती से झूम रहे हैं और नेताजी उनके सामने भोंपू बजा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब जल ही जीवन जल ही मौत बन गया और नेताजी के बयान ने जल पर जलजला लेकर क्या आया। सब जगह पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और मंत्री ने तुरंत यह ऐलान कर दिया कि घंटा कुछ नहीं हुआ। नेता पुत्र तो उनसे भी आगे निकल गया। उसकी जुबान भी शीतलहर से भारी हो गई थी और कहा- जो हो गया सो हो गया। अब क्या कर सकते हैं। खैर, मंत्रीनूमा नेता जी खांस-खांसकर माफी की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सा भूल हो गई हमका माफी दई दो। इधर, आईसीयू के मॉनिटर में खिसकती जिंदगी की रेखाओं को देख मरीज कहने लगे कि अब तो पड़ गई कलेजे में ठंडक। एक वोट की कीमत केवल गंदा मलमूत्र वाला पानी और सहानुभूति के लिए दो लाख ब.....स। कम से कम अगले चुनाव तक तो जीने का लाइसेंस दे देते। यह सुन नेताजी का काफिला अस्पताल से निकला और सीधे स्वीमिंग पूल पहुंच गया और उनका एक पट्ठा झूले पर। शीतलहर में सियासी गर्मी ने इस बारे सारे रिकार्ड ध्वस्त कर दिए और नेताजी डेमेज कंट्रोल में जुट गए। उधर, निगम से हकाले गए अफसरों को दूसरे निगमों और बोर्ड में प्रमोशन देकर पुरस्कार बांट दिए गए। जनता अब भी आईसीयू में हार्ट बिट के लौट आने का इंतजार कर रही है।

विधि कार्य

जयदेव राठी

लेखक बार एसोसिएशन महम (रोहतक) के सदस्य अधिवक्ता हैं।

वकालत पर एआई का बढ़ता प्रभाव कितना कारगर

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट बताती है कि दो हजार तीस तक वैश्विक स्तर पर कानूनी पेशे में तीस से चालीस प्रतिशत नौकरियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रभावित होंगी। भारत जैसे देश में जहां युवा वकीलों को पहले से ही संघर्ष करना पड़ता है, यह भयावह स्थिति होगी। रोजगार के इस संकट से भी बड़ी चिंता न्याय में मानवीय संवेदना के अभाव की है। न्याय केवल कानूनी धाराओं का यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली में लगभग पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं और सर्वोच्च न्यायालय में ही अस्सी हजार से अधिक मामले वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को न्याय प्रणाली में तेजी लाने का समाधान बताया जा रहा है। लेकिन क्या यह समाधान वकालत के पेशे के लिए संकट बनता जा रहा है? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल सहायक उपकरण बनकर रहेगा या धीरे-धीरे वकीलों की भूमिका को सीमित कर देगा? यह प्रश्न आज पूरे कानूनी पेशे के सामने एक गंभीर चुनौती बन गया है।

विश्व स्तर पर कानूनी उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। मैकिन्से की दो हजार तेईस की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक कानूनी कंपनियों में से चवालीस प्रतिशत पहले ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग कर रही हैं। थॉमसन रॉयटर्स की दो हजार चौबीस की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी कानूनी बाजार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित सेवाओं का उपयोग सड़सठ प्रतिशत बढ़ा है। भारत में भी यह प्रवृत्ति तेज हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने दो हजार तेईस में सुप्रेस यानी न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित मंच लॉन्च किया है, जो मामलों की खोज, निर्णयों का विश्लेषण और कानूनी दस्तावेज़ तैयार करने में मदद करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित मामला प्रबंधन प्रणाली को अपनाना शुरू कर दिया है।

परंपरागत रूप से नवीन वकील मामलों की खोज, मामलों का विश्लेषण, पिछले निर्णयों की खोज और प्रारूपण का काम करते थे। आज लेक्सिसनेक्सिस, मनुपात्रा और वेस्टलॉ जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण मिनटों में वह काम कर देते हैं जिसमें पहले दिनों लग जाते थे। रॉस इंटेलिजेंस और केसटेक्स्ट जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच प्राकृतिक भाषा में पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं और संबंधित मामलों के कानून तुरंत प्रदान करते हैं। गोल्डमैन सैक्स की दो हजार तेईस की रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी पेशे में चवालीस प्रतिशत कार्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा स्वचालित हो सकते हैं, जिसमें अधिकतर नवीन वकीलों के काम शामिल हैं।

भारत में जहां हर साल लगभग डेढ़ लाख नए वकील बार परिषद में पंजीकृत होते हैं, वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण उनके लिए प्रारंभिक रोजगार के अवसर सिकुड़ते जा रहे हैं। बड़ी कानूनी कंपनियां अब कम नवीन सहयोगी भर्ती कर रही हैं क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण उनका काम अधिक कुशलता से कर सकते हैं। नियमित कानूनी काम जैसे संविदा समीक्षा, उचित सावधानी और दस्तावेज़ विश्लेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दक्षता मानव वकीलों से कई गुना अधिक है। जेपी मॉर्गन चेज ने कॉइन यानी अनुबंध बुद्धिमत्ता नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम विकसित किया है जो तीन लाख साठ हजार घंटों के मानव कार्य को कुछ सेकंड में पूरा कर देता है।

भारतीय संदर्भ में, संपत्ति मामलों, उपभोक्ता विवादों और सामान्य दीवानी मामलों में काम करने वाले वकीलों को खतरा है। ये मामले अक्सर दस्तावेज़-आधारित होते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इन्हें तेजी से संसाधित कर सकता है। डूनॉटपे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित कानूनी सहायक ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं जब इसने स्वचालित रूप से यातायात टिकट से लड़ने में सफलता दिखाई। हालांकि बाद में नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह एक संकेत था कि साधारण कानूनी सलाह के लिए लोग सस्ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान की ओर रुख कर सकते हैं।

भारत में लॉराटो, माईएडवो और वकीलसर्च जैसी ऑनलाइन कानूनी सेवाएं पहले ही मानव वकीलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संयोजन कर रही हैं। जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिक परिष्कृत होगा, मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होती जाएगी। बार परिषद ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग बाईस लाख पंजीकृत वकील हैं, लेकिन इनमें से केवल पंद्रह से बीस प्रतिशत ही नियमित अभ्यास करते हैं। शेष के लिए काम पाना पहले से ही मुश्किल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से यह स्थिति और खराब हो सकती है।

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट बताती है कि दो हजार तीस तक वैश्विक स्तर पर कानूनी पेशे में तीस से चालीस प्रतिशत नौकरियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रभावित होंगी। भारत जैसे देश में जहां युवा वकीलों को पहले से ही संघर्ष करना पड़ता है, यह भयावह स्थिति होगी। रोजगार के इस संकट से भी बड़ी चिंता न्याय में मानवीय संवेदना के अभाव की है। न्याय केवल कानूनी धाराओं का यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है। यह मानवीय परिस्थितियों, सामाजिक संदर्भ और नैतिक विवेक की समझ की मांग करता है। भारतीय कानूनी प्रणाली में न्याय, समानता और सद्विवेक के सिद्धांत केंद्रीय हैं।

एक वकील केवल कानूनी तर्क नहीं देता, बल्कि मुवक्किल की परिस्थितियों को समझकर मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम इस संवेदना को नहीं समझ सकता। उदाहरण के लिए, गरीबी से प्रेरित अपराध और सुनियोजित अपराध में नैतिक अंतर को समझने के लिए मानवीय विवेक आवश्यक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम उस आंकड़े पर आधारित होते हैं जिन पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। अमेरिका में कॉम्पास नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली, जो अपराधियों की पुनरावृत्ति की संभावना का आकलन करती है, पर आरोप लगे कि यह अश्वेत समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रहित है।

भारतीय संदर्भ में, जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर ऐतिहासिक भेदभाव के आंकड़ों पर प्रशिक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली इन पूर्वाग्रहों को और मजबूत कर सकते हैं। यह संवैधानिक समानता के सिद्धांत के विपरीत होगा। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकांश शोध और विश्लेषणात्मक कार्य करने लगेगा, तो नए वकीलों को गहन कानूनी सोच विकसित करने का अवसर नहीं मिलेगा। यह दीर्घकालिक रूप से पेशे की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। वकालत केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आलोचनात्मक विचार और तर्क-वितर्क की कला है।

वकील-मुवक्किल के बीच गोपनीयता कानूनी पेशे का मूल सिद्धांत है। जब संवेदनशील कानूनी जानकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली में डाली जाती है, तो आंकड़ों की सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है। साइबर हमले, आंकड़ों की चोरी और अनधिकृत पहुंच की संभावनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा दी गई गलत सलाह की जिम्मेदारी किसकी होगी? सॉफ्टवेयर कंपनी की, उसे इस्तेमाल करने वाले वकील की, या अदालत की? यह कानूनी और नैतिक प्रश्न अभी अनुत्तरित है।

यह कहना गलत होगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वकीलों को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर देगा। लेकिन यह निश्चित है कि वकालत का स्वरूप बदलेगा। जो वकील कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपकरण के रूप में अपनाकर अपनी मानवीय क्षमताओं यानी संवेदना, रचनात्मक तर्क और व्यक्तिगत संबंध को मजबूत करेंगे, वे टिके रहेंगे। जटिल संवैधानिक मामले, नवीन कानूनी व्याख्याएं, बहुपक्षीय वाणिज्यिक विवाद और मानवाधिकार मामलों में वकीलों की आवश्यकता बनी रहेगी। लेकिन साधारण, दस्तावेज़-आधारित कार्य के लिए वकीलों की मांग गिरेगी।

इस स्थिति से निपटने के लिए कई आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। विधि महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आंकड़ों के विश्लेषण और तकनीकी कौशल शामिल करने होंगे। बार परिषद को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने होंगे। जिन वकीलों की आजीविका प्रभावित होगी, उनके लिए पुन: प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार के उपाय किए जाने चाहिए। न्याय प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक मानक और जवाबदेही तय करनी होगी। अदालतों में अंतिम निर्णय मानव न्यायाधीशों का होना चाहिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल सहायक भूमिका में रहे।

वकालत का पेशा केवल एक आजीविका नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्तंभ है। वकील नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और न्याय के वाहक हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दक्षता और गति निस्संदेह आकर्षक है, लेकिन न्याय मशीनी नहीं, मानवीय प्रक्रिया है। भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहां भाषा, संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियां अत्यंत भिन्न हैं, वहां मानवीय विवेक की कोई तकनीक विकल्प नहीं हो सकती। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सहायक के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि यह वकीलों का स्थान न ले ले।

सरकार, न्यायपालिका, बार परिषद और कानूनी समुदाय को मिलकर ऐसी रणनीति बनानी होगी जो तकनीक का लाभ उठाए, लेकिन लाखों वकीलों की आजीविका और न्याय की मानवीय आत्मा की रक्षा भी करे। अन्यथा, न्याय में तेजी लाने की कोशिश में हम न्याय की आत्मा ही खो सकते हैं। यह समय की मांग है कि हम तकनीक और मानवता के बीच संतुलन स्थापित करें, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्याय की सेवा करे, न कि उसकी जगह ले ले।

पुस्तक समीक्षा

धर्मपाल महेंद्र जैन

समीक्षक

काहे के अन्नदाता- एक साहित्यिक हस्तक्षेप

हिंदी साहित्य में सुपरिचित मधुर कुलश्रेष्ठ उपन्यास, समालोचना, कविता, कहानी, व्यंग्य आदि विधाओं में निरंतर आवाजाही कर लिख रहे हैं। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित मधुर कुलश्रेष्ठ के चार कहानी संग्रह, छह उपन्यास, दो व्यंग्य संग्रह और एक बाल कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वे ग्रामीण बैंकिंग से जुड़े बहुविध व्यक्तित्व हैं। कई शोधार्थी इनके साहित्य पर अपने प्रबंध प्रस्तुत कर चुके हैं।

उपन्यास का केंद्र बिंदु है वह किसान जिसे संविधान, राजनीति और समाज 'अन्नदाता' कहकर सम्मानित तो करते हैं, पर व्यवहार में उसे कर्जदार और असहाय बना देते हैं। 'काहे के अन्नदाता' समकालीन भारतीय ग्रामीण जीवन, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की त्रासदी का यथार्थवादी दस्तावेज़ है। उपन्यास इस प्रश्न को केंद्र में रखता है कि जो किसान देश का पेट भरता है, वही सबसे अधिक भूखा, असुरक्षित और अपमानित क्यों है।

कहानी मध्यप्रदेश के घटावदा गाँव के इर्द-गिर्द घूमती है। आज़ादी के बाद की सरकारें, योजनाएँ, सहकारी समितियाँ, बैंक, बीज-खाद कंपनियाँ और राजनीति आदि किसान को 'अन्नदाता' कहकर उसकी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन वास्तविकता में वही किसान कर्ज, अपमान और असहायता के दलदल में धँसता चला जाता है। उपन्यास का केन्द्रीय पात्र नत्थुआ दाज्जी है जो एक ईमानदार, मेहनती किसान है, जो खेती को धर्म की तरह मानता है। वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है, कर्ज लेता है, फसल उगाता है, लेकिन हर बार व्यवस्था उसे ठग लेती है। युवा विष्णु के हत्या के बहाने थाने और पुलिस की कार्यविधि में फँसे ग्रामीणों की व्यथा कथा यहाँ है। कोरोना, ऑनर किलिंग, खाद वितरण में भगदड़, खाद की कालाबाजारी, बिजली कटौती, बैंकों की वसूली आदि मिलकर उस व्यवस्था को उजागर करते हैं जो किसान की मदद नहीं, बल्कि और अधिक फँसाने का काम करती है। मध्यप्रदेश के गुना अंचल की मालवी-हाड़ौती मिश्रित बोली कथानक को और गाँव का अम्बेडकर चबूतरा जैसे स्थल उपन्यास को प्रामाणिक बनाते हैं। नत्थू दाज्जी के साथ पूरा गाँव- दलपत, रमको, श्रीलाल, तलुआ, फोटो जर्नलिस्ट दिनेश और ठाकुर इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव के समय किसान 'अन्नदाता' बन जाता है और बाद में सिर्फ 'वोट बैंक' रह जाता है। उपन्यास किसी एक किसान की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय किसान वर्ग की सामूहिक त्रासदी की कथा है।

उपन्यास में नत्थू दाज्जी का चरित्र विशेष महत्व रखता है। वे अनुभव, नैतिकता और विवेक का प्रतीक

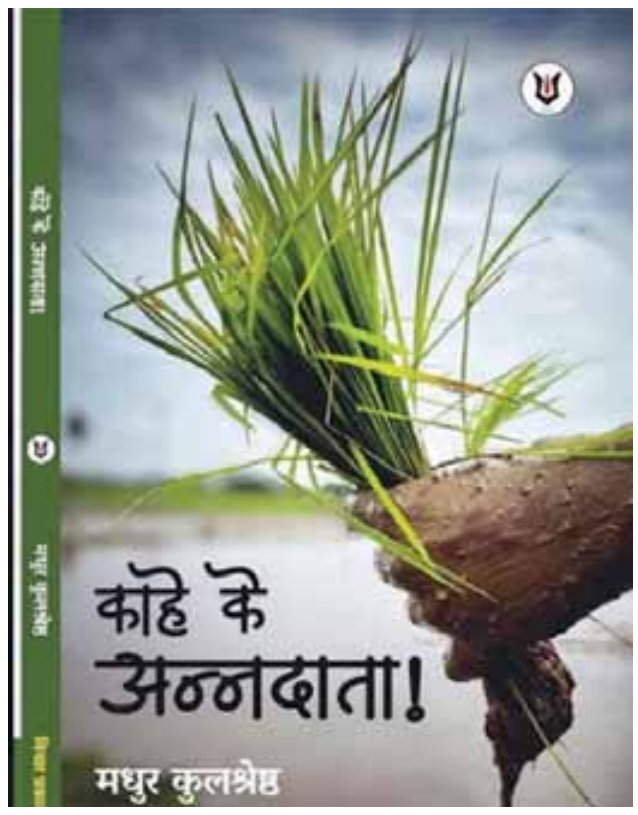

हैं। उनके जीवन से जुड़े रहस्य धीरे-धीरे खुलते हैं, जो यह बताते हैं कि जाति, भूमि और सत्ता की राजनीति ने किस प्रकार मानवीय संबंधों को विकृत किया है। नत्थू दाज्जी के माध्यम से लेखक यह भी दिखाता है कि ग्रामीण समाज में 'प्रतिष्ठा' और 'जाति' कैसे सच्चाई से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

स्त्री पात्रों के माध्यम से लेखक यह दिखाता है कि गरीबी में स्त्री की सुंदरता भी अभिशाप बन जाती है। बेटियों की जवानी और असुरक्षित समाज, एक स्थायी भय की तरह उपस्थित हैं। प्रेम कथाएँ भी हैं, पर वे पूरी तरह विकसित होने से पहले ही जाति, हिंसा और सत्ता की दीवारों से टकराकर नष्ट हो जाती हैं। विष्णु की हत्या उपन्यास का एक ऐसा बिंदु है जो ग्रामीण समाज की सच्चाई से रूबरू कराता है। उपन्यास का अंत प्रकृति की मार, ओलावृष्टि से होता है। लहलहाती फसल का नष्ट होना प्रतीक है किसान की मेहनत, उम्मीद और भविष्य के नष्ट होने का। और वहीं से निकलता है उपन्यास का अंतिम, सबसे मारक प्रश्न- 'जब रूठा ही रहता है भाग्य विधाता, तब काहे के अन्नदाता?' यह उपन्यास किसी एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि पूरे भारतीय कृषक वर्ग का सामूहिक विलाप है।

यदि गोदान किसान की त्रासदी का शास्त्रीय दस्तावेज़ है, तो 'काहे के अन्नदाता' उसका समकालीन, राजनीतिक और आक्रोशपूर्ण विस्तार है। 'काहे के अन्नदाता' कोई 'साहित्यिक प्रयोग' नहीं, बल्कि साहित्यिक हस्तक्षेप है। लेखक सत्ता, नेता और तंत्र पर खुलकर प्रहार करता है। नोटबंदी, कोरोना, किसान आंदोलन, सब जीवित अनुभव की तरह आते हैं। कई संवाद सीधे पाठक के भीतर उतर जाते हैं। डॉ. पानसिंह और डॉ. कुबेर कुमावत के मंतव्य पाठकों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं। यह उपन्यास भावुक नहीं, बल्कि क्रोधित यथार्थ लिखता है। प्रेमचंद की परंपरा में होते हुए भी यह आज के नवउदारवादी भारत का नंगा सच सामने रखता है। यहाँ 'अन्नदाता' शब्द एक खोखला नारा लगने लगता है। किसान आत्महत्या क्यों करता है, यह जानने के लिए इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए।

उपन्यास- काहे के अन्नदाता...
लेखक - मधुर कुलश्रेष्ठ
प्रकाशक - विचार प्रकाशन, ग्वालियर
मूल्य - रु. 225

पर्यावरण

राज कुमार सिन्हा

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

एनजीटी की चेतावनी- बड़े शहरों में जल प्रदूषण का खतरा

मध्यप्रदेश के अधिकांश बड़े शहर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर का पेयजल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नदियों, तालाबों और भूमिगत जल पर निर्भर है। इन सभी स्रोतों पर शहरी सीवेज, औद्योगिक कचरे और ठोस अपशिष्ट का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या तो अपर्याप्त क्षमता के हैं या कई जगह पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। परिणामस्वरूप, आंशिक या बिना उपचारित गंदा पानी सीधे जल स्रोतों में छोड़ा जा रहा है।

भोपाल स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हाल ही में यह स्वीकार किया है कि इंदौर के अलावा राज्य के अन्य बड़े शहरों में भी जल स्रोतों के प्रदूषित होने की गंभीर संभावना मौजूद है। यह टिप्पणी न केवल प्रशासनिक विफलताओं की ओर इशारा करती है, बल्कि प्रदेश के शहरी जल प्रबंधन मॉडल पर भी गहरे सवाल खड़े करती है। एनजीटी की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सीवेज शोधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल स्रोतों की सुरक्षा की व्यवस्था उसी अनुपात में विकसित नहीं हो पाई है। नदियों, तालाबों और भूमिगत जल स्रोतों में बिना उपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह एक स्थायी खतरा बन चुका है। अधिकरण ने कहा कि शहरी सीवेज के अपर्याप्त उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट के अनियंत्रित निस्तारण और जल स्रोतों की नियमित निगरानी के अभाव के कारण यह संकट गहराता जा रहा है। एनजीटी ने राज्य सरकार और संबंधित नगरीय निकायों को जल स्रोतों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।यह टिप्पणी किसी एक दुर्घटना या स्थानीय प्रशासन की चूक भर नहीं है, बल्कि मध्यप्रदेश के अधिकांश शहरों में व्याप्त एक गहरी, संरचनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। नदियों, तालाबों और भूमिगत जल पर निर्भर शहरी आबादी के लिए यह एक चेतावनी है कि संकट अब दरवाज़े पर नहीं, घर के भीतर प्रवेश कर चुका है। जबलपुर में नर्मदा नदी धार्मिक, सांस्कृतिक और पेयजल तीनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन शहर का बड़ा हिस्सा अपना सीवेज सीधे नर्मदा या उसकी सहायक नालियों में डालता है। कई स्थानों पर नालियां बिना किसी शोधन के नदी में मिल रही हैं।

बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है, जब शहर का गंदा पानी सीधे नदी में पहुंचता है। इसके बावजूद नर्मदा को 'स्वच्छ' बताने का सरकारी दावा जमीनी हालात से मेल नहीं खाता। जबलपुर के गोंड काल में बना तालाब कभी स्थानीय लोगों के लिए जल संग्रह और भू-जल रिचार्ज का महत्वपूर्ण स्रोत था। आज वही तालाब शहरी उपेक्षा और प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। तालाब का बड़ा हिस्सा गंदगी, प्लास्टिक कचरे और घरेलू अपशिष्ट से पट चुका है, जिससे यह जल संरचना अब धीरे-धीरे एक कचरा घर में तब्दील हो रही है। यह स्थिति केवल सौंदर्य या पर्यावरण की नहीं, बल्कि सीधे जनस्वास्थ्य से जुड़ा हुआ संकट है। तालाब में जमा सड़ा हुआ कचरा मच्छरों, दुर्गंध और जलजनित रोगों को बढ़ावा दे रहा है। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह तालाब अब राहत नहीं, बल्कि बीमारी का स्रोत बनता जा रहा है। इस तालाब की उपेक्षा केवल स्थानीय समस्या नहीं है। यह पूरे शहर में जल स्रोतों के प्रति उदासीन रवैये को उजागर करती है। जबलपुर जैसे शहर में, जहां नर्मदा जीवनरेखा है, वहां तालाबों का इस तरह बर्बाद होना भविष्य के जल संकट को और गहरा करेगा। ग्वालियर के आस-पास बहने वाली छोटी नदियां और नाले गंदे पानी के लिए मार्ग बन चुकी हैं। नगर क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण अपशिष्ट सीधे नदी और नालों में जा रहे हैं, जिससे नदियों और तालाबों का पानी स्वास्थ्य के लिए खराब हो रहा है। ग्वालियर जिला सहित संभाग में भू-जल का स्तर तेजी से गिर रहा है क्योंकि ज़्यादातर पानी बोरवेल और ट्यूबवेल के माध्यम से निकाला जाता है। ग्वालियर शहर के कई क्षेत्रों में नल का पानी महीनों तक नहीं आता, जिससे लोग बोतलबंद और टैंकर के पानी पर निर्भर रहते हैं। यह जल प्रबंधन और आपूर्ति नेटवर्क के कमजोर होने का संकेत है। ग्वालियर संभाग में जल प्रदूषण और जल संकट दोनों से आम जनता परेशान हैं। मालवा क्षेत्र के बारे में लंबे समय से एक आम कहावत है 'पग-पग रोटी, डग-डग नीर' अर्थात् हर कदम पर भोजन और हर कदम पर पानी। मालवा में इंदौर शहर भी ऐतिहासिक रूप से अपने जल स्रोतों जैसे बावड़ियों, तालाबों और कुओं के लिए जाना जाता था। समय के साथ, जैसे-जैसे इन पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा की गई और नर्मदा जल आपूर्ति परियोजनाओं पर निर्भरता बढ़ गई। यह भी एक सच्चाई है कि एशियाई विकास बैंक(एडीबी) से ऋण सुरक्षित करने के लिए, शहरी सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली को जानबूझकर 'विफल' के रूप में पेश किया गया, ताकि एडीबी की शर्तों के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के नाम पर निजीकरण का रास्ता साफ किया जा सके। एडीबी ऋण की शर्तों में बेहतर प्रबंधन के नाम पर जल आपूर्ति के विभिन्न घटकों के संचालन को निजी कंपनियों को सौंपना शामिल था। इसमें नगर निगम के कर्मचारियों की छंटनी और जल वितरण, बिलिंग और राजस्व संग्रह, संचालन और रखरखाव, मीटरिंग और संबंधित गतिविधियों को निजी फर्मों को आउटसोर्स करना शामिल था। बदले में, नागरिकों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति का सपना दिखाया गया।

सरकार की भूमिका धीरे-धीरे नियामक तक सीमित होती जा रही है। सार्वजनिक जल आपूर्ति पर नगर निगम और स्थानीय निकायों की जवाबदेही धीरे-धीरे कमजोर हो रही है। निजी कंपनियां सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रहती हैं, जिससे पारदर्शिता कम होती है। जनता की शिकायतों का समाधान भी जटिल और धीमा हो गया है।मध्यप्रदेश में पानी का निजीकरण केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा सवाल है। गंभीर सवाल यह है कि नगर निगम और प्रशासन की निगरानी व्यवस्था कहां है?

प्लास्टिक लील गई, गौमाता और उसके नौनिहाल बछड़े को

प्लास्टिक रूपी जहर से कब तक बेजुबान मौत के मुंह में समाते रहेंगे ?

(राजेश शर्मा)

धार। प्रकृति वात्सल्य गौशाला धार में एक ऐसा हृदयविदारक दृश्य देखने को मिला कि हर आंखें नम हो गई। प्लास्टिक की थैलियों (पन्नियों) ने ना केवल माँ को छीन लिया बल्कि ममता के साथ उसके आंचल से लिपट नौनिहाल बछड़े ने भी दम तोड़ दिया। प्रकृति वात्सल्य गौशाला धार में 1 माह पहले गौमाता जो बेहद गंभीर अवस्था में अपने नौनिहाल बछड़े के साथ आई थी। रास्तें में यत्र- तत्र बिखरी पड़ी प्लास्टिक की थैलियों (पन्नियों) का सेवन उस बेजुबान प्राणी की मौत का कारण तो बना ही, दहशत में वह नौनिहाल बछड़ा भी चल बसा...जब पशु चिकित्सकों ने गाय का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके पेट से 40 किलों प्लास्टिक की थैलियां (पन्नियां) निकली।

इस दृश्य को जिसने भी देखा अश्रुधारा बह उठी। अब एक बार फिर बहस उठने लगी है कि प्लास्टिक रूपी जहर का दंश भुगतने के लिए कब तक बेजुबान विवश होते रहेंगे। कब तक मौत के मुंह में समाते रहेंगे ? आधुनिकता की होड़ और दौड़ में हम कब

तक प्लास्टिक रूपी जहर का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देंगे जो इन मूक प्राणियों की मौत का सबब बन जाए। प्लास्टिक के बेहताशा प्रयोग से बिगड़तें पर्यावरण और पशुधन की मौतों ने एक नई बहस छेड़ दी है। चिंता और चिंतन करना होगा हम सब को...

प्रकृति वात्सल्य गौशाला धार के अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी एवं सचिव विजय शर्मा ने बताया कि डेढ़ माह पूर्व गाय बेहद गंभीर अवस्था में बछड़े के साथ गौशाला में लाई गई थी। हमने लगातार उपचार कर इसे बचाने के पूरे प्रयास किए किंतु गंभीर हालत होने के कारण बचा नहीं सके साथ ही मां के वियोग में उसके आंचल का टुकड़ा बछड़ा भी चल बसा। इस हृदयविदारक दृश्य से यह प्रश्न पैदा हो रहा है कि हमने अपने स्वार्थ के लिए प्लास्टिक का ढेर अपने आसपास इतना जमा कर दिया है कि यह प्लास्टिक रूपी जहर न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि बेजुबान जीवों की मौतों का कारण भी बन रहा है। शासन प्रशासन को चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियों पर कढ़ाई से प्रतिबंध लगाया जाए।

मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम बैतूल में लगेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ब्लू एस्ट्रोटर्फ

हॉकी सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ पुर्नस्थापना के लिए 6.97 करोड़ स्वीकृत

बैतूल। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने और खेल सुविधाओं की उपलब्धता के लिए सतत प्रयास कर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने भारतीय हॉकी संघ के शताब्दी वर्ष में जिले के खिलाडियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। श्री खंडेलवाल के प्रयासों से मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम बैतूल में हॉकी सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ की पुर्नस्थापना के लिए 6 करोड़ 97 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के अपर सचिव द्वारा 19 जनवरी को जारी आदेश में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम बैतूल में हॉकी सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ की पुर्नस्थापना के लिए स्टेडियम खेल अधोसंरचना मद से 6 करोड़ 97 लाख रुपए व्यय करने की सहमति दी है। इसके बाद मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम बैतूल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कुछ माह पूर्व स्टेडियम में लगे एस्ट्रोटर्फ के क्षतिग्रस्त होने का हवाला देकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग से मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम बैतूल में सिंथेटिक ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगवाने के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग की थी। बता दे कि वर्ष 2010-2011 में जिला मुख्यालय बैतूल में एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम की सौगात मिली थी। उल्लेखनीय है कि एस्ट्रोटर्फ 10 वर्ष बाद बदला जाना चाहिए, परंतु एस्ट्रोटर्फ के नहीं बदलने से टर्फ क्षतिग्रस्त होने लगा था। जिससे अभ्यास करने वाले खिलाडियों को परेशानी हो रही थी। जिले के वरिष्ठ खिलाडियों द्वारा उक्त समस्या से बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को अवगत करवाकर मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगवाने की मांग की थी। श्री खंडेलवाल ने उक्त मांग को गंभीरता से लेकर भारतीय हॉकी संघ के शताब्दी वर्ष में बैतूल जिले के हॉकी खिलाडियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात देते हुए सिथेटिक ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगवाने के लिए 6 करोड़ 97 लख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई है।

ब्लू एस्टो टर्फ लगने से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी प्रतियोगिताएं

हॉकी खेल जानकारों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन सिंथेटिक ब्लू एस्टो टर्फ वाले स्टेडियम में होता है। बैतूल विधायक श्री खंडेलवाल के प्रयासों से मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम बैतूल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगने के बाद यहां राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिताओं के आयोजन की राह आसान हो जाएगी। साथ ही बैतूल जिले के हॉकी खिलाडियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के स्टेडियम में अभ्यास करने की सुविधा भी जिले में ही मिलने लगेगी।

बड़जात्या (जैन) परिवार द्वारा धार नगर का 29वां नेत्रदान

मणिप्रभा बड़जात्या का स्वर्गवास होने पर परिजनों ने उनके नेत्रदान किए

धार। धार शहर की रघुनाथपुरा निवासी सुरेशचंद्र बड़जात्या (जैन) की धर्मपत्नी एवं रूपेश बड़जात्या की माता जी मणिप्रभाजी बड़जात्या का 73 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुक जाने से स्वर्गवास हो गया था।

ऐसे कठिन समय मे उनके पति और पुत्र द्वारा उनके नेत्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु उनके द्वारा धार मानव सेवा कल्याण समिति से संपर्क किया गया। समिति द्वारा भोज हॉस्पिटल के नेत्र विभाग के डॉ सौरभ बौरासी और उनकी सहायिका कर्मा मुजाल्दा के सहयोग से नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न की गई । नेत्रदान द्वारा दो से चार व्यक्तियों की आँखों में रोशनी प्राप्त होगी। समिति द्वारा इस पुण्य कार्य हेतु बड़जात्या परिवार का आभार व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उल्लेखनीय है की ये धार मानव सेवा कल्याण समिति द्वारा किया गया 29 वां नेत्रदान है।

बगैर पद के भी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वचनबद्ध हूं : सुखदेव पांसे

ग्राम पंचायत बानूर में सीसी सड़क का भूमि पूजन एवं लोकार्पण संपन्न

बैतूल/मुलताई। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने विकासखंड मुलताई की ग्राम पंचायत बानूर में अपने विधायक कार्यकाल के दौरान स्वीकृत राशि से निर्मित सीमेंट कंक्रीट सडक़ का विधिवत लोकार्पण किया। साथ ही उनके प्रयासों से राज्यसभा सांसद एवं सुप्रसिद्ध अधिवक्ता विवेक तंखा द्वारा सांसद निधि से स्वीकृत 200 मीटर सीमेंट कंक्रीट सडक़ निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। इस अवसर पर ग्राम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि वे पद पर रहें या न रहें, सरकार में हों या न हों, क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव

प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही उनका संकल्प है और इसी भावना के साथ वे निरंतर कार्य करते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत बानूर में वर्षों से जर्जर एवं कच्ची सडक़ों की समस्या से ग्रामीण परेशान थे। ग्रामीणों द्वारा इस समस्या से पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे को अवगत कराया गया था, जिस पर उन्होंने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में पूर्व मंत्री पांसे ने राज्यसभा सांसद विवेक तंखा को पत्र लिखकर ग्राम बानूर में 200 मीटर सीमेंट कंक्रीट सडक़ निर्माण हेतु राज्यसभा सांसद निधि से राशि स्वीकृत करने का निवेदन किया था। इस पर सांसद श्री तंखा ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए 6 लाख 6 हजार रुपये की लागत से 200 मीटर सीमेंट कंक्रीट सडक़ निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने सांसद निधि से स्वीकृत सडक़ निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया तथा पूर्व में विधायक निधि से स्वीकृत सडक़ का लोकार्पण भी किया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से यह रहे उपस्थित – सेवादल जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा, कांग्रेस जन समस्या निवारण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तकी-उल-हसन रिजवी, कांग्रेस कमेटी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष किशोर सिंह परिहार, जूनापानी जनपद सदस्य रामदास धुर्वे, ससुंदरा के पूर्व जनपद सदस्य गोलू देशमुख, साईंखेड़ा सरपंच हेमराज गावंडे, उभारिया सरपंच नामदेव पटाहे, जामगांव सरपंच राजू उघड़े, उपसरपंच लीलाधर वर्मा सहित संतोष धोटे, भीमराव पांसे, सुखदेव सोलंकी, मधु देशमुख, धुंधू बुवाडे, साइबू कोरसने, अजबराव कोरसने, ढोढूं पांसे, विठ्ठल बुवाडे, देवराव कोसरने, मनोज पांसे, पंकज पांसे, जयदीप बर्डे, पवन डोंगरे, मनीष गावंडे, आकाश गावंडे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

नपा के सम्मेलन में आज उठेगा एमराल्ड हेरीटेज को कालोनी विकास की अनुज्ञा का मामला

9 हजार 200 वर्गमीटर की रजिस्ट्री और अनुज्ञा 22 हजार 958 वर्गमीटर की

बैतूल। गांधी वार्ड स्थित वर्तमान जेल परिसर में एमराल्ड हेरीटेज को दी गई कालोनी विकास की अनुज्ञा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसे निरस्त किए जाने की मांग हो रही है। नगरपालिका बैतूल में नेता प्रतिपक्ष राजकुमार दीवान ने सीएमओ बैतूल को एक पत्र लिखकर बुधवार को परिषद के सम्मिलन में इस कालोनी विकास की अनुज्ञा पर चर्चा कराए जाने की मांग भी की है। नेता प्रतिपक्ष राजकुमार दीवान का कहना है कि परिषद की बैठक में इस मामले को उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एमराल्ड हेरीटेज को पुर्नघनत्वीकरण नीति के तहत जितनी भूमि की रजिस्ट्री कर स्वामित्व दिया गया है। उससे डेढ़ गुणा ज्यादा जमीन पर उसे कालोनी विकास की अनुज्ञा दे दी गई। जबकि नियम स्पष्ट है कि जितनी भूमि पर स्वामित्व प्राप्त होता है उतनी ही भूमि पर कालोनी विकास

की अनुज्ञा दी जा सकती है। राजकुमार दीवान ने बताया कि शासन ने 3 जुलाई 2024 को 9 हजार 200 वर्ग मीटर भूमि की रजिस्ट्री एमराल्ड हेरीटेज और एसएस अन्नपूर्णा नामक फर्म को की।। वहीं 28 नवंबर 2024 को टीएनसीपी बैतूल ने इस फर्म को उस खसरे में 22 हजार 958 वर्गमीटर की कालोनी विकास की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद नगरपालिका बैतूल ने 22 जुलाई 2025 को 22 हजार 196 वर्ग मीटर में कालोनी विकास की अनुज्ञा दे दी। जबकि उक्त फर्म के पास वर्तमान स्थिति में रजिस्ट्री के अनुसार मात्र 9 हजार 200 वर्ग मीटर का ही आधिपत्य है। दीवान के अनुसार यह एक तरह की धोखाधड़ी है। इस मामले में नपा को तत्काल कालोनी विकास की अनुज्ञा निरस्त करनी चाहिए। उनका कहना है कि इस तरह की अनुज्ञा के कारण नपा को तगड़ी आर्थिक क्षति भी हो रही है। उन्होंने पूरे मामले में अनुज्ञा निरस्त कर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है।

इनका कहना...

यदि ऐसा हुआ है तो कालोनी संबंधी कार्य देखने वाले सब इंजीनियर नगेंद्र वागद्रे इसका परिक्षण करेंगे और नियम के अनुसार अनुज्ञा नहीं है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।

– सतीष मटसेनिया,
सीएमओ नपा बैतूल

प्राधिकार समिति ने एमराल्ड हेरीटेज को पुर्नघनत्वीकरण में जितनी भूमि देना प्रस्तावित किया है। उसके आधार पर टीएनसीपी दी गई। अभी भले ही 9 हजार 200 की रजिस्ट्री की है लेकिन बाकी जमीन भी भविष्य में मिलेगी।

– विनोद परस्ते, सहायक संचालक टीएनसीपी

जो अनुज्ञा दी गई है वह नियमों के विपरित है। अनुज्ञा उतनी भूमि की ही दी जा सकती जितनी की रजिस्ट्री होती है। मुझे ज्ञात हुआ कि यह मामला विधानसभा में भी उठेगा।

– मुकेश लुल्ला,
जेल मामले के जानकार।

नगरपालिका कर्मचारियों का विरोध, वेतन में देरी से आक्रोश

काली पट्टी बांधकर काम शुरू, 26 जनवरी से हड़ताल की चेतावनी

बैतूल। बैतूल नगरपालिका के 250 से अधिक कर्मचारियों ने वेतन में लगातार हो रही देरी के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 26 जनवरी तक उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस विरोध प्रदर्शन में सफाईकर्मी, कार्यालयीन स्टाफ और नगरपालिका की सभी शाखाओं के कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि वेतन में देरी के साथ-साथ उनकी हाजिरी काटने जैसी कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे उनमें और अधिक आक्रोश है। कर्मचारियों ने बताया कि वेतन में देरी के कारण उन्हें अपनी ईएमआई, बच्चों की फीस और अन्य घरेलू खर्चों का भुगतान करने में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन पर राजस्व वसूली बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वे हर साल लगभग 60 प्रतिशत राजस्व लक्ष्य पूरा कर रहे हैं।

खेलों एमपी यूथ गेम्स वर्ष 2025-26 के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित

बैतूल। मप्र शासन खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलों एमपी यूथ गेम्स वर्ष 2025-26 के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता पुलिस ग्राउंड बैतूल में आयोजित की गई। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, समाजसेवी आनंद गिरी, क्रीड़ा अधिकारी सुश्री नीलिमा पीटर, वरिष्ठ पत्रकार संजय द्विवेदी, समाजसेवी अर्जुन सिंह ठाकुर की उपस्थिती में सभी विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में बच्चों को खेल के द्वारा अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला खेल व युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती पूजा कुरील ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकशी, पिट्ठू, खो-खो, बैडमिंटन, शतरंज, योगासन, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती मलखम्ब, टेबल टेनिस एवं टेनिस, बास्केटबॉल आदि खेलों में प्रतियोगिता आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओ के खिलाड़ी, अब खेलो एमपी

यूथ गेम्स के संभाग एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओ में शामिल होगे। प्रतियोगिता में जिला शिक्षा विभाग एवं खेल संघों के संयुक्त समन्वयक से विकासखण्ड स्तरीय चयन स्पर्धा एवं प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न स्थलों जैसे- पुलिस ग्राउंड खेल मैदान, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम व मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम बैतूल, पीएमश्री जयवंती हॉस्कर महाविद्यालय बैतूल में आयोजित की गई। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 10 विकासखण्डों के चयनित प्रतिभागी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन खेल प्रशिक्षक रामनारायण शुक्ला ने किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में नितेश राजपूत द्वारा कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया गया। आयोजन को सफल बनाने में जिला शिक्षा खेल अधिकारी धर्मेन्द्र पंवार, रश्मि बाथरे, गणेश बारस्कर, सहदेव गव्हाडे, उमाकांत कोकाटे, हरिभाऊ झरबड़े बलदेव अरोरा, प्रवीण यादव, सुश्री लक्ष्मी, श्रद्धा, प्रिया पंवार, निरंजन, रविकांत देशमुख, रविन्द्र, सुजित वरकड़े, तरला उईके, महेंद्र सोनकर, तपेश साहू, हेमंत विश्वकर्मा, राधेलाल बनखेड़े, शैलेन्द्र शर्मा, अजय मिश्रा, नरसिंग धुर्वे, अब्दुल खान, गुड्डू काकोडिया, अमित, दुर्गेश, योगिता हारोडे, ललिता धुर्वे, अनारकली तुमडाम, रामप्यारी भारती, रश्मि कश्यप का विशेष सहयोग रहा।

दारू ले लो दारु..कांग्रेस द्वारा आबकारी विभाग के विरुद्ध अनोखा विरोध प्रदर्शन

देवास। कांग्रेस जनों ने शहर के मुख्य मार्ग एम जी रोड से सयाजी द्वार तक हाथ गाड़ी पर शराब की खाली बोतले रख कर घर घर बांट कर विरोध दर्ज किया। देवास में अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे आबकारी विभाग के खिलाफ कांग्रेस ने आज खुला मोर्चा खोल दिया।

शहर के नोवेल्टी चौराहे पर युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसा अनोखा और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया, जिसने पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठेले पर शराब की बोतलें रखकर यह साफ संदेश दिया कि जब विभाग खुद कार्रवाई नहीं कर रहा, तो अवैध शराब अब सड़कों पर खुलेआम बिकेगी। यह प्रदर्शन आबकारी विभाग की लापरवाही और कथित मिलीभगत के खिलाफ सीधा आरोप माना जा रहा है। जितेंद्र सिंह गौड़ ने दो टूक कहा कि युवा कांग्रेस ने 10-15 दिन पहले आबकारी विभाग को ज्ञापन देकर शहर में फल-फूल रहे अवैध शराब कारोबार की पूरी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि कई इलाकों में 'डायरी सिस्टम' के नाम पर शराब बेची जा रही है और शराब दुकानों के आसपास अवैध अहाते खुलेआम संचालित हो रहे हैं, लेकिन विभाग ने अब तक

कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

गौड़ ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग की इस लापरवाही का खामियाजा युवा पीढ़ी और आम जनता भुगत रही है। गली-मोहल्लों में शराब की आसान उपलब्धता समाज को खोखला कर रही है, और विभाग आंख मूंदे बैठा है। युवा कांग्रेस ने साफ शब्दों में मांग की है कि: शराब दुकानों के पास बने सभी अवैध अहाते तुरंत बंद किए जाएँ, शहर में चल रहे डायरी सिस्टम पर सख्त रोक लगे,अवैध शराब बेचने वालों और संरक्षण देने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। जितेंद्र सिंह गौड़ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आबकारी विभाग ने जल्द और प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस पार्टी और भी बड़े, रचनात्मक और उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। आबकारी विभाग के सौजन्य से बेनर बना कर ठेला गाड़ी पर शराब की खाली बोतल रखकर सिग्नेचर लेलो बरकर्डी लेलो, ब्लैक डॉग लेलो, सफेद लेलो, सिग्नेचर लेलो,जैसे नमो को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ द्वारा बताया गया कि देवास शहर में आबकारी विभाग आंख मून कर बैठी है देवास में आपकारी विभाग द्वारा डायरी सिस्टम चालू किया गया जिससे कि देवास में गली-गली में दारू मिल रही है और बताया गया कि अभी भी शराब की दुकानों के पास अहाते चल रहे हैं जो की सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है फिर भी आबकारी द्वारा आज के इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि अब आबकारी विभाग की चुप्पी नहीं चलेगी, और अवैध शराब के खिलाफ लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी।

इस अवसर पर मनीष चौधरी,प्रयास गौतम, मनोज राजानी,ज्ञानसिंह दरबार,हर्षप्रताप सिंह गौड़, दिलीप सिंह,नीरज नागर,ईशान राणा,रूपेश कल्याणे, प्रतीक शास्त्री,सुजीत संगते,कल्याण दरबार, रितेश त्रिपाठी, हफीज घोसी, चिंटू धारू, जाहिद पठान,राहुल पंवार,राजेश राठौर,रोशन रायकवार, नरेंद्र सिंह पंवार,नरेश बैरागी,मोहित राठौर, हर्ष राठौर,मोहित सिंह राठौर, यशवंत कुशवाहा, श्रीकांत चौहान,रोहित डांगी,अजय राठौर, प्रिंस घोड़प्रतापी,असलम,अजय राठौर आदि उपस्थित थे जानकारी बंटू जायसवाल ने दी।

बेटा-बेटियों की मुस्कान में ही मेरी सफलता: सांसद श्री चौहान

केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान सिलवानी विधानसभा में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के क्रिकेट-कबड्डी के फाइनल मुकाबलों में शामिल हुए

रायसेन (निप्र)। केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं विदिशा सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र सिलवानी पहुँचे। इस अवसर पर उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित विधानसभा स्तर के क्रिकेट एवं कबड्डी फाइनल मुकाबलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। फाइनल मुकाबलों से पूर्व सिलवानी स्टेडियम में शिवराज सिंह चौहान ने खिलाड़ियों से आत्मीय मुलाकात की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसके बाद उन्होंने खुले वाहन में स्टेडियम का भ्रमण कर दर्शकों एवं खेल प्रेमियों का अभिवादन स्वीकार किया। पूरे आयोजन में खेल भावना, उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वे अपने बेटा-बेटियों की मुस्कान देखने के लिए हमेशा तरसते हैं और यही मुस्कान उनके जीवन की

हर साल धूमधाम से होगा सांसद खेल महोत्सव

सबसे बड़ी सफलता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि, मेरे लिए बच्चों की मुस्कान ही सब कुछ है। मेरे बेटा-बेटी आगे बढ़ें, यही मामा की असली जीत है।' इसी भावना के साथ उन्होंने यह संकल्प दोहराया कि सांसद खेल महोत्सव अब हर वर्ष पूरे उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन गाँव-गाँव तक पहुंचेगा। *हर साल होगा सांसद खेल महोत्सव* केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अगली बार सिलवानी में आयोजित होने वाला खेल आयोजन एक नए 'खेल महाकुंभ' का रूप लेगा, जहां पहले से बेहतर तैयारी, व्यापक सहभागिता और बड़े स्तर की प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी। *रायसेन में होगा लोकसभा स्तर का खेल महाकुंभ* श्री चौहान ने बताया की कि, 1 और 2 तारीख को रायसेन में लोकसभा स्तर का भव्य खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 तारीख को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे और उसी दिन शाम को रायसेन में पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए खिलाड़ियों के लिए 'मामा' की ओर से सामूहिक डिनर का आयोजन होगा। 2 तारीख को लोकसभा स्तर की प्रतियोगिताओं का फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ टीमें हिस्सा लेंगी। *खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान और प्रोत्साहन* केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि विधानसभा स्तर पर आयोजित क्रिकेट और कबड्डी प्रतियोगिताओं में बेटियों और बेटों- दोनों के लिए समान रूप से पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1,51,000, द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 1,00,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 50,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वहीं लोकसभा स्तर की प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2,51,000, उपविजेता को 2,00,000 तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1,51,000 की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरस्कार राशि वही रहेगी ताकि पूरे संसदीय क्षेत्र के सामने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, 'जो जीते उन्हें भी बधाई, जो दूसरे नंबर पर रहे उन्हें भी बधाई और जो आज नहीं जीत पाए उन्हें भी बधाई, क्योंकि आज की हार ही कल की जीत की नींव होती है। *क्रिकेट और कबड्डी फाइनल में सिलवानी और बेगमगंज ने जीती ट्रॉफी* इस फाइनल मुकाबले में क्रिकेट और कबड्डी दोनों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। क्रिकेट में सिलवानी की टीम विजेता रही, जबकि प्रतापगढ़ की टीम उपविजेता रही। पुरुष कबड्डी में सिलवानी की टीम विजेता रही और प्रतापगढ़ टीम ने उपविजेता स्थान प्राप्त किया। महिला कबड्डी में बेगमगंज की टीम विजेता रही और सिलवानी की टीम उपविजेता रही। इन परिणामों के साथ ही सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई।

संक्षिप्त समाचार

नल से गंदा पानी आने की सूचना मिलने पर कराई जांच

रायसेन (निप्र)। रायसेन नगर के वार्ड नंबर 06 में नल से गंदा पानी आने की सूचना संज्ञान ने आने पर सीएमओ सुरेखा जाटव द्वारा सुपरवाइजर और लाइनमैन को जांच हेतु भेजा गया। सीएमओ सुरेखा जाटव ने बताया कि जांच के दौरान नल चलाकर पानी की जांच की गई। जिसमें पाया गया कि नगर पालिका की पाइपलाइन में गंदा पानी नहीं आ रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित व्यक्ति के घर का नल कनेक्शन टूटा हुआ था और उसमें गंदा पानी जाने से संबंधित व्यक्ति के यहां घर में गंदा पानी पहुंच रहा था। जिसे प्राथमिकता से ठीक करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने 15 लाख की आर्थिक मदद स्वीकृत की

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सिरोंज विधायक श्री उमाकांत शर्मा से प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आधार पर बैरसिया स्थित सरस्वती विद्या बिहार संस्थान के समीप हुई भीषण सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को कुल 15 लाख रुपए की व्यक्तिगत आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। उक्त दुर्घटना में एक लोडिंग वाहन एवं ट्रैक्टर.ट्रॉली के मध्य हुई टक्कर में 05 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी जबकि 10 लोग घायल हुए थे। मुख्यमंत्री द्वारा मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सहायता नियमों को शिथिल किया गया है। स्वीकृत सहायता के अंतर्गत दुर्घटना में मृतकों के निकटतम वैध वारिसों को दो-दो लाख रुपए प्रति व्यक्ति के मान से कुल 10 लाख रुपएए वहीं 10 घायलों को पचास-पचास हजार हजार रुपए प्रति व्यक्ति के मान से कुल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कुल 15 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।मुख्यमंत्री द्वारा दी गई यह सहायता कठिन समय में पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राहत सिद्ध होगी।

विधायक की स्वेच्छानुदान निधि से 55 व्यक्तियों को इलाज हेतु

नर्मदापुरम (निप्र)। विधायक पिपरिया श्री ठाकुरदास नागवंशी की विधायक स्वेच्छानुदान निधि से कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने 55 व्यक्तियों को इलाज हेतु 3 लाख 22 हजार रुपए की सहायता राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक स्वेच्छानुदान निधि से इलाज हेतु तहसील पिपरिया अंतर्गत राज गोस्वामी, अरविंद कुशवाहा, कुंदन सिंह को चार-चार हजार रुपए की चिकित्सा/शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसी प्रकार तहसील बनखेड़ी अंतर्गत सुखदेव उइके, मांगीलाल धुर्वे, अक्षय चौधरी, राज मेहर, लीलाबाई कपाड़िया, आरती किरार, सुषमा बाई ठाकुर, तहसील पिपरिया अंतर्गत सत्यनारायण रघुवंशी, ललित राय, विनीत विश्वकर्मा, नीरज रघुवंशी, महेंद्र सिंह, सविता रघुवंशी, रोशनी, राजू कहार, वर्षा, तुलसी साहू, सीमा बाई, मनोज, छाया, अनिकेत राय, अनीता, कविता कहार, सुखराम अहिरवार, मीना बाथरे, नगर पालिका बनखेड़ी अंतर्गत मधु लता नामदेव, रामप्यारी साहू, अरुण यादव, श्याम यादव, नगर पालिका परिषद पिपरिया अंतर्गत लक्ष्मी कहार, मुन्नी बाई, कामाक्षी नायडू, कविता सोनी, शालिनी अहिरवार, निधि सोनी, ऋतिक भार्गव, पूर्वा तोरणिया, कलाबाई रघुवंशी, सोनू सोनी, पूनम त्रिवेदी, आकाश त्रिवेदी, यशोदा बाथरे को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

आईटीआई नर्मदापुरम में रोजगार एवं स्वरोजगार मेला संपन्न

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) नर्मदापुरम में आयोजित रोजगार एवं स्वरोजगार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र रावत द्वारा दीप प्रज्वलन, सरस्वती पूजन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया।

अपर कलेक्टर श्री रावत ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार मेले के उद्देश्य, महत्व तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कंपनी प्रतिनिधियों के स्टॉल का भ्रमण कर उनसे चर्चा की, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। मेले का सफल संचालन प्रभारी प्राचार्य श्री अनिल देशमुख, जिला रोजगार अधिकारी डॉ. श्याम कुमार धुर्वे एवं जिला रोजगार कार्यालय के प्लेसमेंट ऑफिसर श्री धर्मेश तिवारी के कुशल नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण अधिकारी श्री राहुल अहिरवार, सुश्री दीपिका करारे, श्री आदर्श कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मेले में कुल 130 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। विभिन्न कंपनियों एवं शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनमें से कंपनियों द्वारा 70 छात्र-छात्राओं का प्राथमिक स्तर पर चयन किया गया। वहीं स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 10 प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार कुल 80 युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेले के दौरान 57 छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।

एमआईडीएच योजना के तहत आयोजित किसान प्रशिक्षण का हुआ समापन

सीहोर (निप्र)। इछावर तहसील के भाऊखेड़ी के आजीविका पार्क मैं एकीकृत बागवानी मिशन योजना (एमआईडीएच) के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय किसान प्रशिक्षण सेमिनार का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही किसानों को उद्यानिकी फसलों में लगाने वाले कीट एवं रोग की पहचान और इसके प्रबंधन के उपाय भी बताए गए। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को उद्यानिकी फसलों में तकनीकी का प्रयोग कर बेहतर उत्पादन के तरीकों से अवगत कराया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। किसानों को बताया गया कि वे किस प्रकार अपने उत्पादों की आकर्षक पैकिंग एवं ब्रांडिंग करके

उनकी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को विभागीय योजनाओं, संरक्षित खेती, शेडनेट हाउस, पॉली हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई आदि के बारे में बताया गया। किसानों को आजीविका पार्क का भ्रमण भी कराया गया। कार्यक्रम में डॉ.दीपक कुशवाह, डॉ. निलेश रायपुरिया, डॉ.लालू यादव, सहायक संचालक श्री जगदीश सिंह मुजाल्दा, श्री राजेश वर्मा, श्री सुनील रघुवंशी सहित किसान उपस्थित थे।

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा सोहागपुर विधायक की अनुशंसा पर 05 निर्माण कार्य हेतु

नर्मदापुरम (निप्र)। सोहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह की अनुशंसा पर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा विधायक निधि से विकासखंड माखननगर में 05 निर्माण कार्य के लिए 05 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह की अनुशंसा पर विधायक निधि से विकासखंड माखननगर के ग्राम ग्राम पंचायत मांगरोल के ग्राम ढोंडई में सीसी रोड निर्माण के लिए 02 लाख 50 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीनकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बीकोर में सार्वजनिक चबूतरे के लिए 50 हजार रुपए, ग्राम पंचायत जावली में चबूतरे के सामने पेविंग ब्लॉक के लिए 1 लाख रुपए, ग्राम पंचायत पत्नी में दो अलग-अलग स्थान पर चबूतरा निर्माण के लिए 50-50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

लाड़ली बहना योजना बन रही महिलाओं की आर्थिक मजबूती

सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का नया आधार

सीहोर (निप्र)। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' लगातार बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इसके योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश की लाड़ली बहनों को 1500 रूपये प्रतिमाह की राशि उनके खाते में अंतरित की जा रही है। योजना के माध्यम से मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता ने महिला शक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। महिलाओं को न केवल नियमित सहायता मिल रही है, बल्कि वे अपने परिवार, बच्चों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं में भी अधिक आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। सीहोर फॉरेस्ट कॉलोनी निवासी श्रीमती शालू यादव बताती हैं कि योजना से मिलने वाली राशि ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले स्वयं की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में उन्हें परेशानी होती थी और अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन योजना लागू होने के बाद उन्हें आर्थिक मजबूती मिली और वे स्वयं की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रही हैं। श्रीमती शालू कहती हैं कि नियमित

आर्थिक सहायता से उनके घर की व्यवस्था में स्थिरता आई है और बच्चों की शिक्षा में भी वे सहयोग कर पा रही हैं। उनका कहना है कि यह योजना न केवल आर्थिक लाभ देती है बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। प्रदेशभर में इस योजना ने लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना आज महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण पहल बन गई है। इस योजना के लिए श्रीमती शालू यादव ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद दिया है।

ग्रामोदय से अभ्युदय मध्यप्रदेश अभियान का विकासखण्ड स्तरीय ग्रामोत्सव शुभारंभ

बैतूल (निप्र)। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत बैतूल जिले के समस्त विकासखण्डों में 'ग्रामोदय से अभ्युदय मध्यप्रदेश 'अभियान का विकासखण्ड स्तरीय ग्रामोत्सव शुभारंभ किया गया। सभी विकासखण्डों में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं वरिष्ठ समाजसेवियों की विशेष सहभागिता रही। कार्यक्रम के अंतर्गत युवा संकल्प रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें माननीय अतिथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला समन्वयक श्रीमती प्रिया चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि विकसित भारत -2047 की संकल्पना के साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा जिले में शासन के अन्य विभागों के सहयोग से यह अभियान 12 जनवरी से 26 जनवरी तक पखवाड़े के रूप में ग्रामपंचायत स्तर तक आयोजित किया जा रहा है।

अभियान के अंतर्गत ग्रामोत्सव, रैली, चौपाल, सामूहिक श्रमदान सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आमजन को शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर लाभ लेने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर ग्रामोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर अभियान को प्रभावी रूप दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके द्वारा बैतूल, आठनेर, भैंसदेही एवं भीमपुर विकासखण्डों में आयोजित विकासखण्ड स्तरीय कार्यक्रमों में सहभागिता कर उपस्थित जनसमूह को अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया गया।

खेलो मप्र यूथ गेम्स में हरदा के शौर्य और जय ने तैराकी में जीते पदक, अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करेंगे प्रतिनिधित्व

हरदा (निप्र)। मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहे 'खेलो मप्र यूथ गेम्स' के तहत जिला खेल और युवा कल्याण विभाग, नर्मदापुरम में संभाग स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हरदा जिले के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। ब्लॉक समन्वयक सुश्री सलमा खान ने बताया कि हरदा के शौर्य सोनी ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक और 50 मीटर फ्री स्टाइल में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तथा जय गुर्जर ने फ्री स्टाइल 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रजत पदक प्राप्त किया। इस प्रकार दोनों ही खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई। दोनों खिलाड़ी 27 जनवरी से इन्दौर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हरदा का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन, पुलिस अधीक्षक श्री शशांक, जिला खेल अधिकारी सुश्री उमा पटेल, कोच श्री ज्ञान सिंह फूलरे ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।

18.43 करोड़ की लागत से माचना नदी पर 4-लेन पुल का भूमिपूजन, बैतूल को मिली बड़ी सौगात

सड़क परिवहन, चिकित्सा, रेलवे हर क्षेत्र के विकास में नए आयाम स्थापित: केंद्रीय राज्यमंत्री श्री उइके

बैतूल (निप्र)। केंद्रीय राज्यमंत्री जनजातीय मामले श्री दुर्गादास उईके एवं प्रदेश अध्यक्ष व विधायक बैतूल श्री हेमन्त खंडेलवाल द्वारा रविवार को करबला घाट पर आयोजित कार्यक्रम में 18.43 करोड़ रुपये लागत के बैतूल-खेड़ी मार्ग में माचना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक सर्वश्री महेंद्र सिंह चौहान, श्री चन्द्रशेखर देशमुख, डॉ. योगेश पंडाग्रे, श्रीमती गंगाबाई उईके, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य श्री सुधाकर पवार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, जनपद अध्यक्ष बैतूल श्रीमती इमला बाई जावलकर, पूर्व विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का

मंच संचालन श्री कमलेश सिंह ने किया केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामले श्री दुर्गादास उईके ने कहा कि बैतूल विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल के सतत प्रयासों से बैतूल वासियों को बैतूल से खेड़ी मार्ग में माचना नदी पर पुल की बहुप्रतिक्षित सौगात की आज आधारशिला रखी गई हैं। पूर्व सांसद स्व. श्री विजय खंडेलवाल द्वारा प्रारंभ किए गए विकास कार्यों की पताका आज भी निरंतर लहरहा रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने गांव-गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया था। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सड़क, चिकित्सा, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस अवसर पर विधायक श्री हेमन्त खंडेलवाल ने कहा कि यह बैतूल जिले के लिए ऐतिहासिक और हर्ष का दिन है। बैतूलवासियों की 20-25 वर्षों पुरानी मांग आज साकार होने जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले पुल की प्रस्तावित लागत और चौड़ाई कम थी, किंतु जनभावना और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए राशि 6 करोड़ से बढ़ाकर 18 करोड़ तथा चौड़ाई 30 फीट से बढ़ाकर 60 फीट की गई। इससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि माचना नदी पर स्थित लगभग 120 वर्ष पुरानी पुलिया जिले की धरोहर है, जिसे आवश्यक सुधार कर प्रतिमा विसर्जन जैसे कार्यों में उपयोग किया जाएगा। नया पुल बैतूल शहर के साथ-साथ घोड़ाडोंगरी, भैंसदेही और आठनेर क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। हरदा-इंदौर फोरलेन मार्ग बनने के बाद बढ़ने वाले यातायात दबाव को भी यह पुल सहजता से संभालेगा। विधायक श्री खंडेलवाल ने बताया कि आगामी समय में बैतूल-परतवाड़ा मार्ग तथा बैतूल-आशापुर-बड़वानी-सूरत मार्ग को फोरलेन बनाने की दिशा में कार्य होगा। चूंकि इन सभी मार्गों की कनेक्टिविटी इसी पुल से होगी, इसलिए इसे आने वाले 100 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है।

उन्होंने मंशानुरूप पुल स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक श्री खंडेलवाल ने कहा कि बैतूल के विकास के लिए प्रत्येक परिकल्पना को साकार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग एवं ब्रिज कॉर्पोरेशन के माध्यम से जिले की समस्त सड़कों के उन्नयन के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैतूल को खेलों का हब बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। साथ ही जिले के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कोसमी फेज-2 तथा मोही-चोरपांद्रा औद्योगिक क्षेत्र के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है। विधायक श्री खंडेलवाल ने आगे कहा कि बैतूल नगर की ड्रेनेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क, उद्योग, खेल, पर्यटन, चिकित्सा, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार कर बैतूल को महानगर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैतूल के समग्र विकास के लिए सभी विधायक प्रतिबद्ध हैं और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से बैतूल को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाएगा। विधायक श्री खंडेलवाल ने बैतूल को भविष्य में एक सशक्त और सुव्यवस्थित महानगर के रूप में विकसित करने की रूपरेखा की भी जानकारी दी। एसडीओ ब्रिज श्री गिरीश हिंगवे ने जानकारी दी कि पुल की तकनीकी लागत 10.80 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

रोबोट बताएंगे पानी और सीवर लाइन के लीकेज

पोर्टल और ऐप पर दिखेगा पाइपलाइन नेटवर्क, इंदौर में दूषित पानी से हुई हैं 24 मौतें

भोपाल (नप्र)। इंदौर में दूषित पानी के कारण 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना ने राज्य की शहरी जलापूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मध्यप्रदेश का नगरीय प्रशासन विभाग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है।

अब प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों की वाटर सप्लाई और सीवर लाइन का पूरा रूट-मैप एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे पूरे नेटवर्क की डिजिटल निगरानी संभव हो सकेगी।

413 नगरीय निकाय होंगे कवर- नगरीय प्रशासन विभाग के जीआईएस एक्सपर्ट देवराज त्रिपाठी ने बताया कि अमरुत रेखा नाम का पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसमें प्रदेश की 413 नगरीय निकायों की वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइन

की मैपिंग कर अपलोड की जा रही है। फील्ड इंजीनियर इसकी निगरानी करेंगे।

इंदौर की घटना के बाद अब हम सभी ओवरहेड टैंक (ओएचटी) की मॉनिटरिंग करेंगे। ओएचटी के पैरामीटर के अनुसार प्रॉपर क्लीनिंग कराई जाएगी और उसका वीडियो पोर्टल पर अपलोड होगा। यानी फील्ड पर फिजिकल काम भी होगा और ऑनलाइन निगरानी भी।

रोबोट करेगा लीकेज की पहचान- जहां वाटर और सीवर लाइन आपस में मिलती हैं, उन इंटर सेक्शन पॉइंट्स को पोर्टल पर यलो मार्क से चिह्नित किया जाएगा। जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, वहां रोबोटिक सिस्टम से जांच होगी। बिना खुदाई रोबोट बताएगा कि लीकेज है या नहीं। लीकेज मिलने पर तुरंत सुधार होगा। पहले चरण में सभी 413 नगरीय निकायों के ओएचटी को पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

बिना खुदाई रोबोट सेंस पता लगाएगा

जहां-जहां इंटर सेक्शन पॉइंट होंगे, वहां रोबोटिक सिस्टम से जांच की जाएगी। बिना खुदाई रोबोट सेंस करेगा कि लीकेज है या नहीं। लीकेज मिलने पर तुरंत मरम्मत कराई जाएगी। लीकेज नहीं मिलने पर अगला पॉइंट चेक किया जाएगा। हर यूएलबी क्षेत्र में वाटर सीवर जंक्शन पॉइंट तय किए जाएंगे और नियमित रोबोटिक इंस्पेक्शन होगा।

मोबाइल ऐप से फील्ड मॉनिटरिंग

अमरुत रेखा दो हिस्सों में काम करेगा। वेब पोर्टल में अधिकारियों के लिए पूरा नेटवर्क डेटा मौजूद रहेगा। मोबाइल ऐप के जरिए फील्ड इंजीनियरों द्वारा ग्राउंड वेरिफिकेशन कर रिपेयरिंग कराई जाएगी।

पीएम मोदी के क्रांतिकारी विकास मार्ग पर मध्यप्रदेश अग्रसर : मुख्यमंत्री

पद्मश्री लेखक आलोक मेहता ने मुख्यमंत्री को भेंट की 'मोदी राज के 25 वर्ष' पर केंद्रित पुस्तक

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकास मॉडल को अपनाते हुए प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली में वरिष्ठ संपादक एवं लेखक पद्मश्री श्री आलोक मेहता द्वारा रचित पुस्तक 'रिवॉल्यूशनरी राज - नरेन्द्र मोदीः 25 इयर्स' (कॉफी टेबल बुक) ग्रहण करते हुए यह बात कही।

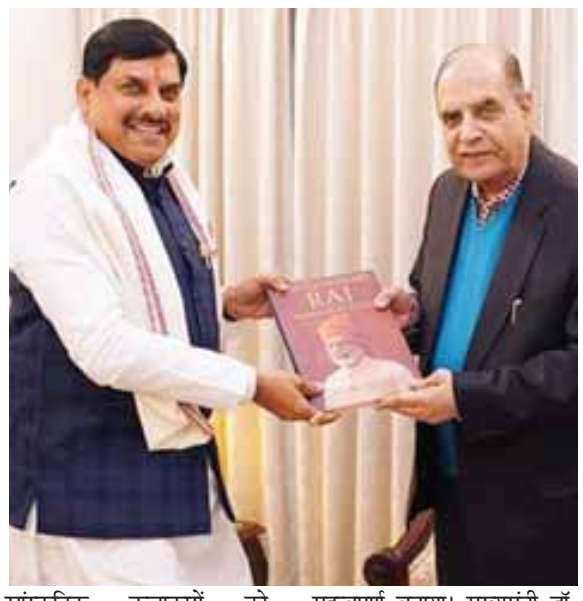

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर देशी-विदेशी निवेश को आकर्षित कर औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्टार्ट-अप्स, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएँ प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं।

यह भेंट-वार्ता दिल्ली से दावोस (स्विट्ज़रलैंड) में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने से पूर्व हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में पुस्तकों और पठन-संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गीता भवन निर्माण योजना में पुस्तकालयों का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पत्रकारों, साहित्यकारों एवं सांस्कृतिक कलाकारों को सामाजिक जागरूकता के लिए हर संभव सहयोग, सहायता एवं प्रोत्साहन देती रहेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुस्तक में उल्लिखित समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं में अनुशासन तथा आत्मनिर्भर विकसित भारत के प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए वे पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने पुस्तक की विस्तृत भूमिका केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लिखे जाने को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री शाह, प्रधानमंत्री के संकल्पों को क्रियान्वित करते हुए आतंकवाद और नक्सल समस्या से प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं, जिससे देश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे विचारों को जन-जन तक पहुँचाने में यह पुस्तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और इसे शिक्षण संस्थानों व पुस्तकालयों तक पहुँचाया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पुस्तक का प्रकाशन शुभी पब्लिकेशंस द्वारा किया गया।

इंदौर में प्रदूषित जल आपूर्ति की समीक्षा के लिए अब राज्य स्तरीय समिति गठित

भोपाल (नप्र)। इंदौर नगर में प्रदूषित जल आपूर्ति के घटनाक्रम की विस्तृत समीक्षा कर निष्कर्ष, सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए राज्य शासन ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री संजय कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। समिति में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री पी. नरहरि, आयुक्त संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास संकेत भोडवे को सदस्य बनाया गया है। आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर श्री सुदाम खाड़े को सदस्य-सचिव नामित किया गया है। समिति द्वारा भागीरथपुरा, इंदौर में घटित घटना के वास्तविक कारणों एवं आवश्यक तथ्यों का परीक्षण करना एवं घटना से संबंधित प्रशासनिक, तकनीकी एवं प्रबंधनगत कमियों का विश्लेषण किया जायेगा। समिति घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस के लिए आवश्यक सुझाव देना और ऐसे अन्य विषय जो जॉच के अधीन मामलों में आवश्यक या अनुषांगिक समझे भी जॉच में शामिल कर सकेगी। समिति संबंधित विभागों से आवश्यक अभिलेख, प्रतिवेदन एवं जानकारी प्राप्त कर सकेगी तथा आवश्यकता होने पर स्थल निरीक्षण भी करेगी।

समिति द्वारा जॉच प्रतिवेदन यथाशीघ्र किन्तु अधिकतम एक माह के

केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह से उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने की सौजन्य भेंट

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर सारगर्भित चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री के दीर्घकालिक सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन के अनुभवों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। श्री शुक्ल ने देशहित से जुड़े विषयों पर उनके विचारों को प्रेरणादायी बताया।

युवक को मंत्री का मुखौटा पहनाकर पुलिस को सौंपा

भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन, अमित शर्मा बोले- विजय शाह को मंत्री पद से हटाया जाए

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल में अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता को मंत्री विजय शाह का मुखौटा पहनाकर उसे हथकड़ी लगाकर पीसीसी के सामने प्रदर्शन किया गया।

कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी से मंत्री का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति को हथकड़ी पहनाए हुए पांच नंबर स्टॉप पर स्थित पुलिस चौकी पहुंचे। यहां मंत्री का मुखौटा पहने व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया।

अमित शर्मा बोले- विजय शाह को पद से हटाया जाए- कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमित शर्मा ने कहा मंत्री विजय शाह ने देश की बेटी सोफिया कुरैशी का अपमान किया। सोफिया ने देश का मान-

सम्मान बढ़ाया और उसे अपमानित करने वाले मंत्री को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बचाने में लगी हुई है। छह महीनों से सरकार लगातार मंत्री को संरक्षण दे रही है।

सुप्रीम कोर्ट में सत्य की जीत हुई- अमित शर्मा ने कहा- मध्य प्रदेश की सरकार जिस मंत्री का संरक्षण कर रही थी उस पर मुकदमा चलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सत्य की जीत हुई है मोहन सरकार की हार हुई है।

हमने प्रतीकात्मक रूप से मंत्री को गिरफ्तार किया- अमित शर्मा ने कहा- हम मंत्री विजय शाह के घर गए थे वे घर से फरार हैं। हमें विजय शाह केरवा के जंगल में घूमते हुए मिले हमने उन्हें प्रतीकात्मक रूप से गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया है।

मंत्री पद से नहीं हटाया तो सीएम का घर घेरेंगे

कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने कहा यदि विजय शाह को मंत्री पद से नहीं हटाया जाता है तो हम मुख्यमंत्री मोहन यादव का घर घेरेंगे।

शाह के नेम प्लेट पर कालिख पोती

इधर, भोपाल युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित खत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के विरोध में मंत्री शाह के बंगले पर कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री की नेम प्लेट पर कालिख पोत कर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया।

खत्री ने कहा कि, मंत्री शाह ने देश की बेटी सोफिया कुरैशी का अपमान किया। सोफिया ने देश का मान-सम्मान बढ़ाया और उसे अपमानित करने वाले मंत्री को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बचाने में लगी हुई है और छह महीनों से सरकार लगातार मंत्री को संरक्षण दे रही है। खत्री ने कहा है कि अगर मंत्री ने पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया तो युवा कांग्रेस उनका सार्वजनिक रूप से मुंह काला करेगी।

आईआईटियन दोस्तों का कमाल

बम्बू से बनी ई-साइकल चलाएंगे बॉलीवुड के स्टार, विदेशों में डिमांड

सतना(नप्र)। कल तक जिस बांस को गांवों में सिर्फ टोकरी, मचिया या सीढ़ी बनाने का जरिया समझा जाता था, आज वही बांस सात समंदर पार अमेरिका, जर्मनी और दुबई के रईस घरों की शान बढ़ा रहा है। यह करिश्मा हुआ है सतना के सोनौरा में, जहां पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक इंजीनियरिंग के संगम ने बांस को 'लक्जरी ब्रांड' में बदल दिया है। सतना के वन विश्राम गृह परिसर में चल रही एक यूनिट ने यह साबित कर दिया है कि अगर सोच नई हो, तो साधारण कच्चे माल से भी इंटरनेशनल मार्केट में राज किया जा सकता है।

सफलता के पीछे आईआईटियन दोस्तों का है दिमाग- इस पूरी सफलता के पीछे दिल्ली के तीन आईआईटियन दोस्त शशांक गौतम, अनंता वर्सने और ट्विंकल वर्सने की सोच है।उन्होंने मिलकर यह सब कर दिखाया है। 2018 में बैंबू मिशन के डायरेक्टर ने उन्हें बांस आधारित बिजनेस का सुझाव दिया था। शशांक ने देखा कि बांस के उत्पाद सिर्फ सड़क किनारे बिकते हैं, उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती कि वे ड्राइंग रूम का हिस्सा बन सकें। बस यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। शशांक गौतम ने बताया कि हम तीन दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया। हमारा मकसद बांस को उस क्लास तक ले जाना था, जहां वह प्लास्टिक या स्टील नहीं, बल्कि लग्जरी आइटम लगे।

मिलिंद सोमन के लिए बन रही 'बैंबू ई-साइकिल'- इस यूनिट का सबसे नायब उत्पाद बांस से बनी ई-साइकिल है। यह साइकिल दिखने में किसी महंगी धातु की लगती है, लेकिन इसका फ्रेम बांस का है। यह स्टील जितनी मजबूत है, मगर वजन में बेहद हल्की। एक बार चार्ज करने पर यह करीब 100 किमी तक दौड़ती है। इसकी स्पीड 25 किमी/घंटा है। हालांकि इस साइकिल की कीमत अभी डिसाइड नहीं हुई है। यह साइकिल आईओटी और बैटरी सिस्टम से लैस है। बॉलीवुड की फिटनेस आइकॉन और सुपरमॉडल मिलिंद सोमन ने अपने लिए यह साइकिल ऑर्डर की है। इसके अलावा अभिनेत्री सोनम कपूर, पूजा भट्ट एवं अन्य कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी यहां के प्रोडक्ट मंगवा चुके हैं।

अमेरिका-जर्मनी और यूएसए तक पहुंच रहा प्रोडक्ट- वहां काम करने वाले कर्मचारी पुष्पराज वरुण ने मीडिया को बताया कि यहां डिजाइनर लैंप, सोफा, डाइनिंग टेबल, पेन होल्डर समेत 50 से ज्यादा उत्पाद बनते हैं। इनकी कीमत 4000 रुपए से शुरू होकर लाखों तक जाती है। इनकी फिनिशिंग इतनी शानदार है कि दुबई, मलेशिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूएसए जैसे देशों से लगातार ऑर्डर आ रहे हैं।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बड़ा खेल

उप संचालक पर फर्जी बिल और अवैध खनन के आरोप, होगी बड़ी सुनवाई

उमरिया (नप्र)। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार बाघों या हाथियों की मौत से नहीं, बल्कि एक बड़े घोटाले के आरोपों से। उप संचालक प्रकाश कुमार वर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और सरकारी पैसों को गलत तरीके से खर्च किया। सामाजिक कार्यकर्ता सुशील लेवी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को एक विस्तृत शिकायत सौंपी है। उन्होंने कई वित्तीय अनियमितताओं, अवैध खनन और सरकारी संसाधनों के निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

क्या है पूरा मामला?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में उप संचालक प्रकाश कुमार वर्मा पर पद के दुरुपयोग और शासकीय राशि के गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी सुनवाई 20 जनवरी को होगी। आरोपों में 16 करोड़ की विकास निधि में से 4-5 करोड़ के अनियमित व्यय, काल्पनिक बिलों के माध्यम से गबन, और निजी लाभ के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, प्रतिबंधित क्षेत्रों में रात में सफारी कराने और वन्यजीवों के गायब होने की घटनाओं की भी जांच की जाएगी।

कंपनियों के नाम पर बनाए फर्जी बिल- शिकायत के अनुसार, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विकास निधि के लिए लगभग 16 करोड़ रुपये का बजट था। इसमें से 4 से 5 करोड़ रुपये कथित तौर पर गलत तरीके से खर्च किए गए। आरोप है कि एन.एच. इंडस्ट्रीज और महालक्ष्मी ट्रेडर्स जैसी कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसों का गबन किया गया। यह भी कहा गया है कि इन कंपनियों के संचालकों के उप संचालक प्रकाश कुमार वर्मा से पारिवारिक और निजी संबंध हैं। इसका सबूत नीरज तिवारी के शादी के कार्ड से मिलता है, जिसमें प्रेषक के रूप में श्रीमती किरण वर्मा और श्री प्रकाश कुमार वर्मा का नाम लिखा है।

आरटीआई से मांगी थी जानकारी- वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत 17 जनवरी 2025 को श्री प्रकाश कुमार वर्मा की जाति संबंधी जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई।

खनन के भी लगे आरोप

शिकायत में यह भी बताया गया है कि एक निजी बोलेरो गाड़ी, जिसका मालिक एन एच इंडस्ट्रीज का नीरज तिवारी है, को बिना किसी अनुबंध के सरकारी काम में दिखाया गया। इसके लिए हर महीने 20 हजार रुपये किराया और टाइगर रिजर्व से डीजल दिया गया। इसके अलावा, निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले रेत और मिट्टी के लिए बिना रॉयल्टी और ट्रांजिट परमिट के बिल पास किए गए, जो कि मध्यप्रदेश खनिज नियमों का सीधा उल्लंघन है। आरोप है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के नदी-नालों से अवैध रेत और मिट्टी का खनन भी कराया गया।

नाइट सफारी और अन्य गंभीर आरोप

वन्यजीव संरक्षण से जुड़े मामलों पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि प्रतिबंधित इलाकों में रात के समय सफारी कराई गई। बाघों और अन्य वन्यजीवों के गायब होने की घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं।

सीनियर्स ने दिए जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश ने जांच के आदेश दिए हैं। राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर इस जांच को 20 जनवरी 2026 को दोपहर 4 बजे करेगा। संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी कागजात के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है। पत्र में यह भी लिखा है कि शिकायतकर्ता का पता और मोबाइल नंबर शिकायत में नहीं है, इसलिए अगर उनकी जानकारी मिलती है तो उन्हें जांच की तारीख और समय के बारे में बताया जाए।

रायसेन अस्पताल की नर्सों ने पुलिस चौकी में लगाया ताला

प्रधान आरक्षक पर अभद्रता का आरोप, कार्रवाई की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर पहुंची

रायसेन (नप्र)। रायसेन जिला अस्पताल में नर्सों ने प्रधान आरक्षक पर अभद्रता का आरोप लगाया। नर्सों ने मंगलवार को अस्पताल परिसर स्थित पुलिस चौकी पर ताला जड़ दिया। नर्सों ने प्रधान आरक्षक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

अस्पताल परिसर में नर्सों के साथ डॉक्टरों ने भी नारेबाजी की आरोप है कि ड्यूटी के दौरान प्रधान आरक्षक कृष्ण पाल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से तीन दिन पहले की गई थी। हालांकि, शिकायत के बावजूद प्रधान आरक्षक पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्वास्थ्यकर्मी आक्रोशित हैं।

विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचीं- प्रशासन की उदासीनता से नाराज होकर नर्सों ने पुलिस चौकी को बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारी नर्सों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरोपी प्रधान आरक्षक पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे काम बंद कर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगी।

भोजशाला में बसंत-पंचमी पर दिनभर पूजा की मांग

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 22 जनवरी को सुनवाई, शुक्रवार होने से पूजन और नमाज के चलते टकराव

धार (नप्र)। धार की भोजशाला में बसंत पंचमी के अवसर पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति के लिए हिंदू पक्ष ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका की सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने (हरिशंकर जैन के सहयोग से) दिल्ली में यह याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है।

याचिका में मांग- याचिका में मांग की गई है कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन भोजशाला परिसर में केवल हिंदू समाज को दिनभर मां सरस्वती की पूजा करने की अनुमति दी जाए। चूंकि इस दिन शुक्रवार है, इसलिए याचिका में मुस्लिम समुदाय की जुमे की नमाज पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।माहौल खराब न हो इसलिए

भोजशाला में भारी पुलिस बल तैनात है।

50 प्रतिशत फोर्स धार पहुंची- आईजी अनुराग ने बताया कि पुलिस की तैयारी पूरी है। 8 हजार का बल बसंत पंचमी के पहले धार पहुंच जएगा। 50 प्रतिशत फोर्स धार आ चुका है। फोर्स डिप्लॉय का प्लान भी बन चुका है। हम सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखेंगे। हमने थ्रीडी मैपिंग भी कराई है, जिससे हर परिस्थिति का पता चलेगा। अधिकारियों को बताने में भी सुविधा रहेगी। वहीं, बाइक पार्टी व मोबाइल पार्टी द्वारा भी नजर रखेंगे। सभी मोहल्लों पर पुलिस की नजर है।

इधर, भोजशाला परिसर में भी सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ा दी गई है। परिसर में 24 घंटे पुलिस जवानों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। वहीं, वॉच टावर के साथ चौकी भी बनाई है। परिसर में जिग-जैग लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। बसंत पंचमी पर लोगों को जिक-जैग से गुजरने के बाद भोजशाला में प्रवेश मिलेगा। यहां जगह-जगह पर पुलिस की तैनाती रहेगी। फिलहाल हिंदू पक्ष पूरे दिन पूजा-पाठ और मुस्लिम पक्ष नमाज को लेकर अड़े हुए हैं।